भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड , आगरा (उ.प्र.) एवं धौलपुर (राजस्थान) से एक साथ प्रसारित

सच टाइम्स

DAINIK SACH TIMES

वर्ष 18 अंक 132 | मुरैना,गुरूवार 20 अगस्त 2026 | पृष्ठ - 8 मूल्य 1.50 ₹

श्योपुर में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का शक्ति प्रदर्शन!

पेज : 03

जनजातीय संस्कृति, पहचान और ज्ञान-परंपरा पर प्रभाव

पेज : 04

सड़क हादसों को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

पेज : 06

भरौली थाने की कमान नवागत टीआई राय ने संभाली, चार्ज संभालते ही दिए कड़े संकेत

पेज : 07

कई घरों के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि बहुत महत्व रखती है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बहनों के सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के लिए उनकी मदद जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया संदेश में किए विचार व्यक्त

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि कई घरों के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि बहुत महत्व रखती है। इस राशि से कई घरों में सकारात्मकता और सुविधा का संचार हुआ है। कई बहनों ने निरंतर प्राप्त हो रही इस राशि के आधार पर अपने स्तर पर आय के स्रोत विकसित किए है। कई बहनें सिलाई मशीन या गोपालन के माध्यम से घर की आय में योगदान दे रही हैं। लाड़ली बहना योजना से कई घरों का आर्थिक तंत्र बदला है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता-पिता के परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जाना, बहनों के जीवन का एक चुनौती पूर्ण पक्ष है। नए परिवार में अपना स्थान बनाना, स्नेह और अपने सामर्थ्य से नए परिवार की धुरी बनना, बहनों की हिम्मत को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बहनों की थोड़ी मदद उनके सम्मान और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। राज्य सरकार बहनों के जीवन में सुख समृद्धि लाने और उनके सपनों को साकार करने में मदद के लिए ही लाडली बहना योजना संचालित कर रही है। बहनों की छोटी-छोटी जरूरतें उनकी राह में कभी रुकावट ना बने, वे आत्मनिर्भर बनें हमारा यही प्रयास है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले भोपाल में मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह, इंस्टाग्राम पर बढ़ाएं सक्रियता, युवाओं से सीधे संवाद पर जोर

नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी है। खासतौर पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अधिक मौजूदगी दर्ज कराने और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक में मंत्रियों को केवल 'एक्स' तक सीमित न रहते हुए इंस्टाग्राम पर पहुंच बढ़ाने और सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनहित से जुड़े कार्यों को रील्स और अन्य रचनात्मक माध्यमों के जरिए युवाओं तक पहुंचाने की सलाह दी गई।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की सोशल मीडिया सक्रियता को लेकर विस्तृत आकलन पेश किया गया। मंत्रियों को सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग दी गई। खास बात यह रही कि मंत्रियों का आकलन केवल एक-दूसरे के मुकाबले नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की सोशल मीडिया पहुंच और प्रभाव के मुकाबले भी किया गया।

यह मूल्यांकन 1 मई से 15 अगस्त 2026 के बीच इंस्टा, एक्स और फेसबुक पर नेताओं की गतिविधियों के आधार पर किया गया। इसमें पोस्ट की संख्या, कुल और औसत एंगेजमेंट, लाइक्स तथा फॉलोअर्स जैसे मानकों को शामिल किया गया।

आकलन में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर रहे।

प्रधानमंत्री मोदी खुद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से संवाद करते रहे हैं। सरकार की कोशिश अब मंत्रियों की डिजिटल मौजूदगी को और प्रभावी बनाकर खासकर युवा वर्ग तक सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी पहुंचाने की है।

संक्षिप्त समाचार

सीबीआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप लेखा नियंत्रक को 10 लाख रुपये घूस लेते पकड़ा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत उप लेखा नियंत्रक संदीप को 10 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने एक निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण की फाइल को जल्द निपटाने के लिए पहले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद वह 10 लाख रुपये लेने पर सहमत हुआ। सीबीआई के अनुसार, आरोपी उप लेखा नियंत्रक संदीप (आईसीएएसः 2020) के खिलाफ मंगलवार को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। वह यहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण से जुड़ी फाइल उसके पास लंबित थी और उसे जल्द निपटाने के लिए आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। जांच एजेंसी ने मंगलवार को जाल बिछाया और आरोपी को उसकी पत्नी के जरिए 10 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। सीबीआई ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

सपा नेता आजम खान से जुड़े रामपुर से दिल्ली तक 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

लखनऊ, 19 अगस्त (हि.स.)। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बुधवार को आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। रामपुर से लेकर सहारनपुर और दिल्ली तक 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर से जुड़ी मनीलॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में है। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत ईडी की कार्रवाई चल रही है। जांच में कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच पैसे के लेनदेन और अन्य जानकारियां मिली हैं।

गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने की भेंट

नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली के सर्वांगीण विकास, सुशासन, जनकल्याण और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर गृह मंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और दिल्ली विकास के नए प्रतिमान स्थापित करे, इस दिशा में उनके व्यापक अनुभव और सुझाव अत्यंत प्रेरक रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रसेवा और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण हम सभी को निरंतर कर्तव्यपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री के मुफ्त कोचिंग पहल को लेकर शिक्षा मंत्री ने की बैठक

नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय शिक्षा और खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की पहल को लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत राष्ट्रीय मंच बनाना है, जिससे देशभर के छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी की सुविधा मिल सके।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में इस मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, 'कोचिंग कक्षाएं गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ हैं। हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएंगे।'' बैठक का उद्देश्य देशभर के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यवस्थित परीक्षा तैयारी की सुविधा पहुंचाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों से इस पहल को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा छात्रों की जरूरतों के अनुरूप ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से देश के अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराना है।

वन, वन्यजीव और समुदायों की रक्षा को सफलता का पैमाना बनाएं : उपराष्ट्रपति

देहरादून, 19 अगस्त (हि. स.)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने वन, वन्यजीव और स्थानीय समुदायों की रक्षा को सफलता का पैमाना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और भारत के सभ्यतागत ज्ञान का समन्वय सतत भविष्य के निर्माण की कुंजी है।

उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के परिवीक्षार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में इन अधिकारियों पर देश के वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत2047 की दिशा में

आगे बढ़ते हुए भारतीय वन सेवा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में वन सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

राधाकृष्णन ने अधिकारियों से संरक्षण और विकास, पारिस्थितिक सुरक्षा और आजीविका और वर्तमान आवश्यकताओं और भावी पीढ़ियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता से अधिक महत्वपूर्ण टीम की उत्कृष्टता है और निरंतर सामूहिक प्रयासों से ही मजबूत संस्थानों और राष्ट्र का निर्माण होता है।

उन्होंने वनों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ पीढ़ियों से सामंजस्य बनाकर रहने वाले समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाना आवश्यक है।

कोलकाता होटल अग्निकांड में मारे गए नौ लोगों में पांच बांग्लादेशी नागरिक

कोलकाता, 19 अगस्त (हि.स.)। कोलकाता के धर्मतला इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में मंगलवार रात लगी आग में मारे गए नौ लोगों में पांच बांग्लादेशी नागरिकों के होने की जानकारी सामने आई है। कोलकाता स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग के उप उच्चायुक्त मोहम्मद खालिद ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, कोलकाता पुलिस की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, मृत पांच बांग्लादेशी नागरिकों में चार कुष्टिया और एक ढाका के सावर इलाके का रहने वाला था। मृतकों की पहचान कुष्टिया निवासी देवाशीष दत्त, शर्णशिष दत्त, अफसाना शिम्मिन, मोहम्मद अकरम अली और ढाका के सावर निवासी अहमद बाबू के रूप में हुई है। इनमें शर्णशिष की उम्र महज तीन वर्ष थी।

जानकारी के अनुसार, देवाशीष दत्त अपनी पत्नी अफसाना शिम्मिन और तीन वर्षीय बेटे शर्णशिष के साथ बेंगलुरु गए थे। बच्चे के इलाज के बाद तीनों मंगलवार को ही कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने धर्मतला के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन होटल में कमरा लिया था। उसी रात होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें तीनों की मौत हो गई।

बांग्लादेश उप उच्चायोग के एक अधिकारी ने स्थानीय थाने और मुर्दाघर पहुंचकर मृतकों की पहचान की। स्थानीय पुलिस की सहायता से पांचों की बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचान की गई। उप उच्चायुक्त मोहम्मद खालिद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

उल्लेखनीय है कि धर्मतला के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन होटल में मंगलवार रात भीषण आग लग गई थी। आग और धुएं के कारण होटल में फंसे नौ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। घटना के बाद होटल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस ने युवाओं की स्थिति, चढ़ावा चोरी व सीमा सुरक्षा पर सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में युवाओं की स्थिति, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों से इन सभी मुद्दों पर गहनता से विचार कर राज्यों के विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए तैयारी करने की अपील की। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी प्रमुख शीर्ष नेता मौजूद रहे। खरगे ने कहा कि संसद सत्र के बाद पहली बार हम सब मिल रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता युवाओं की है। सरकार की गलत नीतियों ने युवाओं को हताशा और बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। शिक्षा और रोजगार की उपेक्षा, पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। कांग्रेस युवाओं के लिए स्पष्ट और समयबद्ध एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को केंद्र में रखकर वोटिंग की उम्र घटाई, नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क बनाया और शिक्षा नीति में रोजगार एवं कौशल विकास को जोड़ा। कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा और आईटी क्रांति से देश को नई दिशा दी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की थी और जनता ने ईमानदारी की उम्मीद से दान दिया, लेकिन वहां भारी घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री को आस्थावान जनता से माफी मांगनी चाहिए और स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा अतिक्रमण से जुड़े गंभीर तथ्य सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने ईमानदारी से जानकारी देने की बजाय खबरों को गलत बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनदेखी भी नहीं हो सकती। गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री का बयान न कोई घुस आया है और न कोई घुसा हुआ है आज भी सवालों के घेरे में है। खरगे ने कहा कि युवाओं का भविष्य, जनता की आस्था और देश की सीमाएं तीनों सवाल सरकार की जवाबदेही से जुड़े हैं।

स्वामी एवं प्रकाशक रविन्द्र सिंह नवरंग द्वारा वनखंडी रोड़ हरीराज टॉकीज के पीछे, शिवनगर मुरैना (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक नवीन बंसल द्वारा बंसल ऑफसेट रामजानकी मंदिर के पास, जीवाजीगंज मुरैना से मुद्रित, स्थानीय संपादक- धर्मेंद्र सिंह ''सीताराम जी '', मुरैना, मोबाइल 6261839476
RNI No. MPHIN/2009/45558 फोन 07532-232387 मोवा- 9425334744 तथा सभी विवादों को न्याय क्षेत्र मुरैना ही होगा। डाक पंजीयन चंबल क्रमांक जी-13-2/163/RNP/2025-27, email : sachtimes101@gmail.com Website -https//sachtimes.in, https//sachtimes.in/epaper/

नवांकुर सखी यात्रा से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

विजयपुर (निज संवाददाता)। ग्राम किंजरी ब्लॉक विजयपुर में नवांकुर संस्थाकौशिकी सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी गसवानी के द्वारा-मध्य प्रदेश जन अभियान राज्य कार्यालय के निर्देशन पर जिला समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह एव ब्लाक समन्वयक श्रीमति नीतू सिंह गौतम के आदेशानुरसार सेक्टर गसवानी विकासखंड विजयपुर अंतर्गत नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन नवांकुर संस्था गसवानी के सेक्टर क्रमांक 05 गसवानी विजयपुर के ग्राम किंजरी मै नवांकुर सखी हरियाली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत किजरी के सरपंच श्री धर्मेन्द्र आदिवासी जी रूरस्र स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री जसराम धाकड जी कोशिकी सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट सोसायटी के सचिव श्री दिलीप तिवारी जी अध्यक्ष श्री दुर्गेश गोस्वामी जी प्रस्पुटन समिति का अध्यक्ष श्री बीरू शर्मा जी सचिव श्री दीपक गोस्वामी ,परामर्शदाता राकेश जाटव तथा गसवानी क्षेत्र की समस्त आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण महिला पुरुष तथा स्कूल की छात्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम रूरस्र स्कूल में किया गया । यहां पर मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती की छाया प्रतिमा पर माल्यार्पण एव कन्या पूजन रोली का तिलक लगाकर एवं कलश पूजन कर यात्रा का आयोजन किया गया ।इसके पश्चात सभी नवांकुर सखियों को तिलक लगाकर उनके सिर पर कलश रख कर यात्रा निकाली गई । यह यात्रा ग्राम किजरी के द्व/ह्य स्कूल से किजरी मोहनपुर के प्रमुख मार्गो से होती हुई द्व/ह्य एव श्च/ह्य स्कूल पर पहुंची इस यात्रा में नवांकुर सखियां अपने सिर पर कलश रखे हुए एवं पर्यावरण संरक्षण के गीत एवं भजन गाते हुए चल रही थी , साथ में देशभक्ति के नारे भी समिति के पदाधिकारी लगा रहे थे ,जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे ,इस यात्रा के माध्यम से ग्राम वासियों को नवांकुर सखियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव जागृत करने का संदेश दिया गया । यात्रा अर्पित किया गया ,यहीं पर नवांकुर सखियों एवं यात्रा में सहभागी समुदाय के साथ बैठक में नवांकुर संस्था के संचालक श्री दिलीप तिवारी जी नवांकुर सखी यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा नारी शक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है महिलाएं जब पर्यावरण से जुड़ती हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है यात्रा में वितरित पौधों को घर आंगन में लगाकर उनकी देखभाल बच्चों की तरह करें तभी इस अभियान की सफलता है । जन अभियान परिषद द्वारा चलाए जा रहे हरियाली यात्रा कार्यक्रम में नारी शक्ति के माध्यम से सुरक्षित आधार पर पर्यावरण संरक्षण को बड़ा बढ़ावा देने वाली सराहनीय मुहिम है ।इस अवसर पर बोलते हुए सरपंच श्री धर्मेन्द्र आदिवासी द्वारा बताया कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढियों के लिए जीवन सुरक्षित करने का संकल्प है । परामर्शदाता राकेश जाटव व प्रस्पुटन समिति बड़ौदा कला अध्यक्ष श्री महेंद्र परिहार के द्वारा कहा गया वृक्ष हमें प्राणवायु , छाया , फल , औषधि और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, इसलिए पौधारोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की निरंतर देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है । आज दिए गए पौधों को आप अपने घर पर ले जाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर प्रचार -प्रसार करें । इस कार्यक्रम में परामर्शदाता राकेश जाटव प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष वीरू शर्मा एवं बड़ी संख्या में गांव के युवा तथा नवांकुर सखियां उपस्थित रही । कार्यक्रम के अंत में नवांकुर सखी अभियान के अंतर्गत सभी नवांकुर सखियों को 21- 21 पौधों का वितरण किया गया । तथा अतिथियों की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया । अंत में प्रसाद वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया आभार प्रदर्शन दुर्गेश गोस्वामी द्वारा किया गया।

संस्था द्वारा तिरंगा यात्रा ब दहेज प्रथा एवं दांडी मार्च पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन

गुना। (निज संवाददाता)। संस्था रचित युवा मंडल राघोगढ़ जिला गुना के द्वारा संस्कृति संचनालय भोपाल मध्य प्रदेश के सहयोग से 14 अगस्त 2026 को तिरंगा यात्रा निकाली गई एवं संस्था कार्यालय सांडा कॉलोनी राघोगढ़ माता मंदिर के परिसर में 15 अगस्त 2026 को संस्था के अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया उसके उपरांत सांडा कॉलोनी के बच्चों बेटा एवं बेटियों द्वारा दहेज प्रथा दांडी मार्च राष्ट्र गीत देशभक्ति पर नुक्कड़ नाटक ब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री विष्णु पाराशर जी रहे विशिष्ठ अतिथि समाज सेवी ब मंदिर के पुजारी श्री मिंटू महाराज जी एवं अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री प्रबल व्यास जी ने की मंच का संचालन संस्था सचिव श्री सौमित्र तिवारी ने किया कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती जी एवं माता मंदिर में दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया उसके बाद अतिथियों एवं कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत बंधन अभिनंदन किया गया उसके बाद छात्र एवं छात्राओं ब कलाकारों द्वारा लोक गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया जिसमें दहेज प्रथा के प्रति संदेश दिया गया उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च (नमक सत्याग्रह) इस अवसर पर युवाओं को आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण विरोध का महत्व समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महोदय श्री पाराशर जी द्वारा लोगों को अवगत कराया कि हमें दहेज प्रथा से बचना चाहिए विशिष्ट अतिथि महोदय श्री पुजारी जी द्वारा बताया गया की संस्था हमेशा मंदिर परिसर में कार्यक्रम करती रहती है और हम संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं संस्था अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस हार्दिक बधाई दी एवं बच्चों ने जो कार्यक्रम किया इससे लोगों को सीख भी मिली और अपेक्षाएं राखी के बच्चे ऐसे ही साथ देते रहें को संस्था अच्छे कार्यक्रम और भी कराएंगे उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी बच्चों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार वितरण किए गए कोषाध्यक्ष। महोदय जी ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया उसके बाद सभी लोगों को स्वल्पाहार वितरण किया गया ब मुख्य अतिथियों का सोल श्रीफल देकर आभार व्यक्त किया गया

थाना कोतवाली पुलिस व्दारा थाना क्षेत्र में सट्टे के खिलाफ कार्यवाही केते हुये अलग-अलग स्थानो से दो आरोपियो को सट्टा खिलवाते हुये धर दबोच कर सट्टा अंक पर्चियाँ व 4430 रु. जप्त किये किये

शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया जी के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थो, जुआ एवं सट्टा के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन कुमार धुर्वे के मार्ग निर्देशन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे व्दारा टीम गठित की गयी जो टीम व्दारा दिनांक 18.08.26 को थाना कोतवाली क्षेत्र में छापामार कार्यवाही करते हुये अलग अलग स्थानो कालीमाता मंदिर के पास मनियर रोड से आरोपी करन पुत्र मोहन उम्र 31 साल नि0 टोंगरा रोड फतेहपुर को पकडा आरोपी से 2 सट्टा अंक पर्ची एक डोट व 950रु. जप्त किये एवं रेन बसेरा के पास बस स्टेण्ड शिवपुरी से आरोपी हर्ष पुत्र कैलाश उम्र 21 साल नि0 फतेहपुर को पकडा आरोपी से 2 सट्टा अंक पर्ची एक डोट व 3480रु. जप्त किये आरोपीगण से कुल 4430रु. जप्त किये बाद आरोपीगण के विरुध्द अप.क्र. 639/26, 640/26 धारा 4क सट्टा अधिनयम का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया सट्टा खिलवाने वालो के विरुध्द कोतवाली पुलिस व्दारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

सराहनीय भूमिका:. उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक रोहित दुबे, प्र.आर. 348 बाबूलाल नागर, प्र. आर. 806 रविकुमार की भूमिका रही।

eHRMS में ई-अटेंडेंस के विरोध में आज से कलम बंद हड़ताल करेंगे कृषि विस्तार अधिकारी...

शिवपुरी (निज संवाददाता) म.प्र. कृषि विस्तार अधिकारी संघ, जिला इकाई शिवपुरी ने अपनी विभिन्न मांगों और द्ग॥ज्ञ्रस् प्रणाली में लागू की जा रही ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में कलमबंद कार्य बहिष्कार का ऐलान किया

है। संघ द्वारा 17 अगस्त 2026 से 20 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ?इस संबंध में संघ ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपकर शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति मांगी है। प्रदर्शन के दौरान सभी कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड स्तर पर अपनी उपस्थिति केवल ऑफलाइन दर्ज कराएंगे।

संघ की प्रमुख मांगें:

ई-अटेंडेंस से राहत: eHRMS प्रणाली के तहत लागू की जा रही अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जाए।

ग्रेड-पे में वृद्धि: कृषि विस्तार अधिकारियों को ?2800 ग्रेड-पे का लाभ प्रदान किया जाए।

भत्ते में बढ़ोतरी: अतिरिक्त केंद्र का कार्यभार संभालने पर मिलने वाले वर्तमान 500 के स्थान पर ?5,000 प्रति माह भत्ता दिया जाए।

संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक, अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगा तथा शासन के नियमों का पालन किया जाएगा।

जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी व शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने एसपी से गुहार...

नरवर (शिवपुरी) /(निज संवाददाता)। पुलिस थाना नरवर क्षेत्र के ग्राम खोड बावड़ी निवासी पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी), कलेक्टर एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर जानलेवा हमले के फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। पीड़ित देशराज गुर्जर ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष रंजिश के चलते उन पर झूठा केस दर्ज कराने का षड्यंत्र भी रच रहा है।

घटना का विवरण व मुख्य आरोप

जानलेवा हमला: 16 अगस्त 2026 की रात करीब 10:30 बजे बल्लू गुर्जर, महेंद्र, धर्मेंद्र, कल्लू, सुरेंद्र (पुत्र लक्ष्मण), औतार (पुत्र राजाराम) सहित अन्य आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग की और मारपीट की। इस मामले में पुलिस थाना नरवर में अपराध क्रमांक 153/2026 दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी रंजिश के कारण अपने ही परिवार के व्यक्ति नारायण (पुत्र कमल सिंह) को स्वयं कट्टे से गोली मारकर चोटिल कर रहे हैं, ताकि फरियादी पक्ष पर धारा 109 ब्रहस् के तहत झूठा क्रॉस-केस दर्ज कराया जा सके।

पुराना आपराधिक रिकॉर्ड: पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी पहले भी 27 जून 2026 को मारपीट (अपराध क्रमांक 110/2026) तथा वर्ष 2025 में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट (अपराध क्रमांक 258/2025) जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं।

मुख्य मांगें आरोपी सुरेंद्र गुर्जर और औतार गुर्जर के 12 बोर बंदूक के शस्त्र लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं। हत्या के प्रयास (धारा 109/307 BNS/IPC) के तहत नामांकित फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।

आरोपियों द्वारा गढ़े जा रहे झूठे मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए।

थाना सिरसौद पुलिस द्वारा किसानों से टमाटर की फसल खरीदने एवं पैसे नहीं देकर अमानत में खयानत करने के आरोपी करन कुमार को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेअह किया....

शिवपुरी (निज संवाददाता) फरियादी विनोद पुत्र उम्मेद सिंह रावत उम्र 26 साल निवासी ग्राम रामखेडी थाना सिरसौद जिला शिवपुरी ने रिपोर्ट किया कि मैं रामखेडी में अपने खेतों में टमाटर की खेती करता हूँ। व्यापारी करन कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी जजीरपुर कासगंज उत्तर प्रदेश, मेरे टमाटर से भरी कुल क्रेट 317 कीमती 362070 रूपये की ले गया है जिसमें से मेरे टमाटर के 100000 रूपये उक्त व्यापारी करन कुमार के द्वारा दे दिये हैं एवं शेष 262070 रूपये उस पर वकाया थे, जिनको व्यापारी करन कुमार द्वारा टमाटर के पैसे न देकर मेरे साथ अमानत में खयानत कर धोखा किया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमति यांगचेन डोलकर भूटिया जी के द्वारा अपराध की गम्भीरता को देखते हुये तथा किसानों के साथ अमानत में खयानत का अपराध होने से आरोपी को अति शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी पोहरी आनंद राय एवं थाना प्रभारी सिरसौद को निर्देशित किया गया था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री आर.डी. प्रजापति के एवं एसडीओपी पोहरी श्री आनंद राय के कुशल मार्गदर्शन में टीम गठित की गयी। आरोपी की सही जानकारी प्राप्त करने में सायबर सेल शिवपुरी की मदद ली गई। आरोपी को पकडने हेतु पुलिस टीम को नागपुर महाराष्ट्र भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश मे नागपुर महाराष्ट्र पहुंचकर लोकल पुलिस थाना अजनी जिला नागपुर महाराष्ट्र की मदद से आरोपी करन कुमार पुत्र रघुवीर सिंह जाटव उम्र 35 साल निवासी नगला समस थाना काशगंज जिला काशगंज उ.प्र. को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय शिवपुरी पेश किया गया है। कार्यवाही में उनि धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर थाना प्रभारी सिरसौद, उनि धर्मेन्द्र सिह जाट प्रभारी सायबर सेल शिवपुरी, उनि जगदीश भिलाला, प्रआर. 351 वलवंत पाल, प्रआर. 798 सत्यवीर जादौन, प्रआर 216 विक्रम वाथम, आर। 116 जलज रावत. आर 1181 दामोदर परिहार, आर 315 विकाश सिंह चौहान, आर.चा. 917 रमेश सिंह, की अहम भूमिका रही।

शिवपुरी में यातायात पुलिस द्वारा आज हैप्पी डेज स्कूल में यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया

शिवपुरी (निज संवाददाता)।शिवपुरी जिसमें छात्रों को यातायात नियमों, रहवीर योजना, हिट एंड रन योजना एवं पीएम राहत योजना के बारे में जानकारी दी गई।

छात्रों को हेलमेट की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। वर्ष 2025 में शिवपुरी जिले में बिना हेलमेट धारण किए हुए दो पहिया वाहन चालकों की 410 सड़क दुर्घटना में 67 लोगों की मौत हो गई एवं शिवपुरी जिले में 1 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक कुल 223 सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट धारण किए हुए 61 लोगों की मौत हो गई।

यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है।

छात्रों को आंकड़ों सहित हेलमेट की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई एवं उन्हें हेलमेट धारण करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, हैप्पी डेज की डायरेक्टर श्रीमती गीता जी दीवान, प्रिंसिपल अंजू शर्मा एवं समस्त छात्र उपस्थित थे।

हाथ में जूते, पैरों में कीचड़... शिक्षक बोले- 'लेट क्यों होते हो बेटा?' वार्ड-1 बछोरा में सड़क बनी बच्चों की रोज की परीक्षा

शिवपुरी (निज संवाददाता) शहर के वार्ड नंबर 1 बछोरा में बारिश के दिनों में सड़क की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालात यह हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को हाथ में जूते लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। बच्चे किसी तरह रास्ता पार करने के बाद जूते पहनकर स्कूल पहुंचते हैं।

बच्चों के मुताबिक, कीचड़ और खराब रास्ते के कारण कई बार उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। स्कूल पहुंचने पर शिक्षक कहते हैं, 'बेटा जल्दी आया करो, लेट क्यों होते हो?' लेकिन बच्चों की परेशानी यह है कि रास्ता खराब होने के कारण समय पर स्कूल पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।

इसी रास्ते से महिलाएं शंकर जी के मंदिर में पूजा-पाठ करने जाती हैं। बारिश के दौरान उन्हें भी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले ग्रामीणों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। इसके बावजूद बारिश में रास्ते की हालत बदतर हो जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की पढ़ाई, मंदिर जाने वाली महिलाओं और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सड़क का जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि हर बारिश में उन्हें

शिवपुरी कलेक्टर ने किया करैरा क्षेत्र के ग्राम थनरा और दबरा सहित विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण....

जनजातीय बस्ती में सुनीं समस्याएं, समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष कैंप लगाने के निर्देश

उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी में मिलीं गंभीर खामियां; सीएचओ व कार्यकर्ता को हटाने के निर्देश

शिवपुरी (निज संवाददाता)। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज विकासखंड करैरा के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य, स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा जनसुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनिमियताओं और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने संबंधितों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने ग्राम दबरा (दिनारा) स्थित जनजातीय बस्ती का पैदल भ्रमण कर जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बस्तीवासियों के बीच बैठकर उनसे सीधा संवाद किया तथा बिजली, पेयजल, राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित समस्याएं सुनीं। मौके पर ही जनसमस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने तत्काल पटवारी को स्थल पर बुलवाया और फौती

नामांतरण, किसान सम्मान निधि, पेंशन तथा राशन जैसी सुविधाओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों व महिलाओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण, आरबीएसके स्वास्थ्य शिविर के आयोजन तथा बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को मौके पर आकर ग्रामीणों को जागरूक करने एवं तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बस्ती क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने आबकारी अधिकारी को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसमस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण हेतु उन्होंने अधिकारियों को बस्ती में ही विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।

ग्राम दबरा (दिनारा) स्थित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के औचक निरीक्षण के दौरान केंद्र में लापरवाही पाई गई। बच्चों के पोषण और देखभाल से जुड़ी अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बाल विकास परियोजना अधिकारी को संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में मध्याह्न भोजन के सुचारु एवं पारदर्शी संचालन का जिम्मा स्थानीय समूह को सौंपने के सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के उप स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में अनिमियतताएं पाई गईं। निरीक्षण के समय स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी तथा पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का कक्ष बंद पाया गया। इसके साथ ही वह बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाई गईं। आमजन की सेहत और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर वर्मा ने अनुपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सूचना

मेरे ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक mp 06/001628/06 में गलती से मेरा नाम AIDTYA singhal पिता sh.DINESH singhal अंग्रेजी में हो गया है जो कि गलत है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम (ADITYA singhal) आदित्य सिंघल पिता (DINESH chandra singhal) दिनेश चंद्र सिंघल है जो की सही है इसे आगे से लिखा एवं पढ़ा जावे!

ADITYA singhal s/o Dinesh Chandra Singhal

श्योपुर में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का शक्ति प्रदर्शन!

कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने का संकल्प, 2028 के विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी—'एकजुट होकर जनता के बीच जाएं, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करें'

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। शहर के बायपास रोड स्थित शुभम कॉम्प्लेक्स के पास कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, सामाजिक न्याय और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला प्रभारी कृष्ण गोपाल चौरसिया, अनुसूचित जाति विभाग ग्वालियर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मांगीलाल फौजी एवं विधायक बाबू जंडेल मौजूद रहे। सभी प्रमुख वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया।

कार्यकर्ताओं को दिया 'जनता के बीच जाने' का मंत्र

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की असली ताकत कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को आपसी एकजुटता के साथ जनता के बीच सक्रिय रहकर उनके मुद्दों और समस्याओं को उठाना होगा।

अनुसूचित जाति समाज से जुड़े अधिकार, सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाने तथा आमजन की समस्याओं को संगठन के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनता के संपर्क में रहकर संगठन को मजबूत किया जाए।

2028 के चुनाव को लेकर अभी से बिगुल!

सम्मेलन में आगामी 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया गया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने और कांग्रेस को मजबूत जनसमर्थन दिलाने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने की बात कही गई।

कार्यकर्ताओं से अपील—संगठन को बूथ तक मजबूत करो

बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, जनहित से जुड़े मुद्दों और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया।

अनुसूचित जाति समाज के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का फोकस

सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति समाज से जुड़े अधिकारों और सम्मान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की गतिविधियों को और तेज करने पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन की पहुंच बनाना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को गांव, वार्ड और बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

नवल किशोर चौबे के नेतृत्व में आयोजित हुआ सम्मेलन

कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष नवल किशोर चौबे द्वारा किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस एवं अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया।

सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने बढ़ाया राजनीतिक उत्साह

सम्मेलन में दौलत राम गुप्ता, बृजेश गहरवार, मानसिंह राठौर, चीनी कुरैशी, अशोक धूलिया, विजय सिंह धूलिया, कांति देवी, कृष्णा राठौर, मनवार बाई, मोतीलाल बैरवा, रामस्वरूप बैरवा, मथुरा लाल बैरवा, बजरंग लाल बैरवा, हरिमोहन बैरवा, रामप्रसाद बैरवा, रामकिशन बैरवा, ओमप्रकाश बैरवा, कन्हैया लाल बैरवा, रामदयाल बैरवा, पार्षद सुमेर सिंह, रामकुमार उमरिया, पहलवान सिंह, मोहनलाल बैरवा, बल्लू बैरवा, राकेश बैरवा, हरिओम बैरवा, रोशन लाल खरे, राजीव सगर, देवीशंकर बैरवा, शुगर सिंह जाटव, अतर सिंह जाटव, राजकुमार बैरवा, कुलदीप जाटव, जगदीश बैरवा, रामलखन बैरवा, बलवान बैरवा, सूरज कुमार बैरवा, सोनू बैरवा, महावीर बैरवा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

श्योपुर से कांग्रेस ने दिया चुनावी संदेश—अब संगठन को जमीन पर उतारने की तैयारी

कार्यकर्ता सम्मेलन भले ही अनुसूचित जाति विभाग के संगठनात्मक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया हो, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना रहा है।

कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। अब सम्मेलन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कितनी सक्रियता दिखाते हैं और संगठन इस अभियान को किस तरह आगे बढ़ाता है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।

फिलहाल श्योपुर में अनुसूचित जाति विभाग के इस सम्मेलन ने कांग्रेस के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियों की हलचल जरूर तेज कर दी है।

गाड़ी लगाने की मामूली बात पर खूनी संघर्ष! तलवार से हमला, महिलाओं समेत चार घायल

सलापुरा क्षेत्र में पड़ोसियों का विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदला, वाहनों में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप—घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। शहर के सलापुरा क्षेत्र में गाड़ी लगाने की बात को लेकर शुरू हुआ पड़ोसियों का मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान तलवार से हमला किए जाने और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना में महिलाओं सहित चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गाड़ी लगाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी

जानकारी के अनुसार सलापुरा क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच गाड़ी लगाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में हुई कहासुनी देखते ही देखते बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया।

आरोप है कि इसी दौरान अंजार नक्शेवाले और उनके परिवार पर तलवार से हमला किया गया। हमले में परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। घटना के दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है।

महिलाओं समेत चार लोग घायल

घटना में महिलाओं सहित कुल चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

घटना की सूचना फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई।

तलवार से हमला और वाहनों में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप

विवाद के दौरान तलवार के इस्तेमाल और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जिस विवाद की शुरुआत महज गाड़ी लगाने की बात से हुई, वह इतनी तेजी से हिंसक रूप ले लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।

घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवादों को समय रहते शांत नहीं किया जाए तो वे कितनी जल्दी गंभीर संघर्ष का रूप ले सकते हैं।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ विवाद के कारणों और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि विवाद की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे।

सलापुरा की घटना के बाद पुलिस के सामने चुनौती

सलापुरा क्षेत्र की इस घटना के बाद पुलिस के सामने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चुनौती है। वहीं घायलों के उपचार के साथ पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की भी पड़ताल कर रही है।

गाड़ी लगाने जैसे मामूली विवाद से शुरू हुआ यह संघर्ष अब पुलिस जांच के केंद्र में है।

नए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के आते ही नशे के कारोबार पर शिकंजा!

स्मैक बेचने वालों की तलाश में पुलिस की दबिश, जुगनू उर्फ जहीर खान गिरफ्तार; राजू पठान की तलाश जारी—अपराध और चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की सक्रियता बढ़ी

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले की पुलिस कमान संभालने के बाद नए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के नेतृत्व में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के साथ-साथ नशे के कारोबार के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। खासतौर पर युवाओं को प्रभावित कर रहे स्मैक के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस टीमों ने स्मैक की बिक्री से जुड़े संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की, जिसमें जुगनू उर्फ जहीर खान को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, स्मैक बिक्री के मामले में राजू पठान निवासी हसनपुरा हवेली, श्योपुर तथा जुगनू उर्फ जहीर खान निवासी हम्माल मोहल्ला, बड़ा इमामबाड़ा, श्योपुर की तलाश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजू पठान की तलाश जारी बताई गई है।

संभावित ठिकानों पर पुलिस की दबिश

स्मैक की बिक्री के संबंध में सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों को चिन्हित कर दबिश की कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है।

नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त संदेश

श्योपुर में लंबे समय से नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई जाती रही है। खासकर स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पुलिस द्वारा संभावित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशीले पदार्थों की बिक्री और अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चोरी की घटनाओं पर भी निगरानी बढ़ाने का दावा

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के नेतृत्व में पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चोरी की घटनाओं और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त एवं निगरानी बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

हालांकि जिले में अपराध और चोरी पर पूरी तरह रोक लगने का दावा आधिकारिक आंकड़ों और तुलनात्मक अपराध रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन पुलिस की हालिया सक्रियता से अपराधियों पर दबाव बढ़ने का संदेश जरूर गया है।

अब सवाल—स्मैक की सप्लाई लाइन तक कब पहुंचेगी पुलिस?

स्मैक के खिलाफ कार्रवाई में किसी एक आरोपी की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन असली चुनौती इसके पीछे सक्रिय पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचने की है।

पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं—

स्मैक कहां से श्योपुर पहुंच रही है?

इसकी सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं?

स्थानीय स्तर पर इसे किन क्षेत्रों में बेचा जा रहा है?

नशे के कारोबार में और कितने लोग जुड़े हैं?

क्या पुलिस कार्रवाई सप्लायर और मुख्य नेटवर्क तक पहुंच पाएगी?

यदि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशते हुए नेटवर्क की जड़ तक पहुंचती है, तो जिले में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

जुगनू गिरफ्तार, राजू पठान की तलाश

फिलहाल पुलिस के अनुसार जुगनू उर्फ जहीर खान गिरफ्तार हो चुका है, जबकि राजू पठान की तलाश जारी है। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ और आगे की कार्रवाई में नशे के कारोबार से जुड़े कितने चेहरे बेनकाब होते हैं और स्मैक की सप्लाई लाइन कहां तक जाती है।

श्योपुर पुलिस की यह कार्रवाई यदि लगातार अभियान का रूप लेती है तो नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

रात में बॉर्डर चौकी पर पहुंचे एसपी मोती उर रहमान, जलालपुरा से बड़ौदा थाने तक औचक निरीक्षण

कानून-व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी, लंबित मामलों की समीक्षा; पुलिसिंग में लापरवाही पर सख्ती के संकेत

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग की जमीनी स्थिति परखने के लिए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान का मैदानी भ्रमण लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार रात एसपी ने स्टेट बॉर्डर चौकी जलालपुरा और थाना बड़ौदा का निरीक्षण किया। देर रात हुए इस निरीक्षण से पुलिस महकमे में भी सक्रियता देखने को मिली।

एसपी ने चौकी एवं थाने में पहुंचकर वहां की पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों से मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

बॉर्डर चौकी पर विशेष नजर

जलालपुरा चौकी श्योपुर जिले की महत्वपूर्ण सीमा चौकियों में शामिल है। ऐसे में एसपी का रात के समय यहां पहुंचकर निरीक्षण करना पुलिस व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है।

निरीक्षण के दौरान चौकी की कार्यप्रणाली, पुलिस स्टाफ की मौजूदगी तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। सीमा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और निगरानी को प्रभावी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

बड़ौदा थाने में लंबित मामलों की खुली फाइल

जलालपुरा के बाद एसपी मोती उर रहमान ने थाना बड़ौदा का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की तथा लंबित मामलों की जानकारी ली।

एसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। पुलिस कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़े, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

रात का निरीक्षण, पुलिस महकमे को साफ संदेश

एसपी का लगातार थाना और चौकियों का भ्रमण पुलिसकर्मियों के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

विशेषकर ऐसे समय में जब पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं पर अंकुश और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात सामने आ रही है, एसपी का लगातार मैदानी निरीक्षण पुलिसिंग को सक्रिय रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अब सिर्फ थाने में बैठकर नहीं, मैदान में उतरकर होगी पुलिसिंग!

एसपी मोती उर रहमान द्वारा लगातार थाना, चौकी और सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किए जाने से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। लंबित मामलों के निराकरण से लेकर कानून-व्यवस्था की निगरानी तक पुलिसिंग को सक्रिय रखने का प्रयास दिखाई दे रहा है।

जलालपुरा बॉर्डर चौकी से लेकर बड़ौदा थाना तक एसपी के रात्रिकालीन निरीक्षण ने साफ संकेत दिया है कि जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय अब केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी स्थिति पर भी नजर रख रहा है।

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पति और तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी

बड़ौदा थाना क्षेत्र में रात के समय हुई घटना से सनसनी—महिला की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ FIR, पुलिस जांच में जुटी

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर/बड़ौदा। बड़ौदा थाना क्षेत्र में सोमवार रात घर में घुसकर एक महिला से कथित छेड़छाड़ और उसके पति व तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना रात करीब 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, बड़ौदिया बिंदी निवासी रामचरण मीणा और सीताराम मीणा पर आरोप है कि वे महिला के घर में उस समय घुसे, जब उसका पति खेत पर गया हुआ था।

महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों व्यक्ति उसके घर में घुसे और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला द्वारा शोर मचाए जाने के बाद दोनों मौके से चले गए।

महिला का यह भी आरोप है कि जाते समय दोनों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी तो उसके पति और तीनों बच्चों को जान से खत्म कर देंगे।

डर के बावजूद पति को बताई घटना

बताया गया है कि घटना के दौरान महिला का पति खेत पर गया हुआ था। रात में जब वह घर लौटा तो महिला ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मंगलवार सुबह महिला अपने पति के साथ बड़ौदा थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस ने शुरू की जांच

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच, घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

महिला की शिकायत के बाद कार्रवाई

घर में घुसकर महिला से कथित छेड़छाड़ और परिवार को धमकी दिए जाने की घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा किया है। पुलिस के सामने अब मामले की निष्पक्ष जांच के साथ आरोपों की सत्यता सामने लाने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है।

महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुरैना में बैंक मैनेजर और दलालों द्वारा महिला के साथ ठगी का मामला

मुरैना (निज संवाददाता)। मुरैना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर और तीन दलालों ने मिलकर एक अशिक्षित महिला के साथ 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है मुरैना के बड़ोखर क्षेत्र की गोस?वामी गली में रहने वाली संगीता शर्मा एक दुकान पर नौकरी करती हैं। दुकान पर आने-जाने वाले दलालों (इमरान खान, संतोष और संतोषी लाल गौर) ने उन्हें मकान बनाने के लिए 8 लाख रुपये का आवास लोन दिलाने का झांसा दिया। वे संगीता को बैंक ऑफ इंडिया की एमएस रोड ब्रांच के मैनेजर अनुराग तिवारी के पास ले गए, जहाँ अशिक्षित होने के कारण संगीता से कई कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। मैनेजर और दलालों ने मिलीभगत कर उनके नाम पर 8 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया और राशि कूटेशन वाले फर्म के खाते में ट्रांसफर कर हड़प ली।संगीता को इस धोखाधड़ी की भनक तब लगी जब 16 अक्टूबर 2025 को बैंक के रिकवरी सेक्शन से उनके मोबाइल पर लोन की किस्त जमा करने के लिए फोन आया। जब उन्होंने बैंक जाकर जानकारी ली, तब पता चला कि उनके नाम पर लोन उठ चुका है जबकि उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला था।इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की, जिसकी जांच में मामला सही पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने बैंक मैनेजर अनुराग तिवारी और तीनों दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

संपादकीय

बुजुर्गों की छत पर अब बच्चों का अधिकार नहीं, माता-पिता की गरिमा सर्वोपरि

कभी जिस घर की नींव माता-पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, त्याग और सपनों से रखी थी, उसी घर में यदि बुढ़ापे में उन्हें अपमान, भय और असुरक्षा का सामना करना पड़े, तो सवाल फिर स्वभाविक तौर पर संपत्ति से आगे यह मनुष्य की गरिमा का बन जाता है। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को सामने आया निर्णय इसी बुनियादी प्रश्न को केंद्र में लाता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बढ़ती उम्र किसी व्यक्ति को असुरक्षित, अपमानित या अपने ही घर में बेबस होकर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यदि बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं या उनके भरण-पोषण और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को बाधित करते हैं, तो 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत गठित ट्रिब्यूनल परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है।

अब एक तरह से देखा जाए तो यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक से आगे बढ़कर उस सामाजिक उद्देश्य को देखा है, जिसके लिए वरिष्ठ नागरिक कानून बनाया गया था। बुजुर्गों को सिर्फ भोजन और आर्थिक सहायता के साथ ही सम्मान, सुरक्षा और रहने की सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।

उक्त मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता से जुड़ा है। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को अपनी संपत्ति से हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया था। यह संपत्ति उन्होंने स्वयं खरीदी थी। विवाद की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को उस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया, किंतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन आदेशों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की व्याख्या यह थी कि 2007 का कानून वरिष्ठ नागरिक को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत के सामने मूल प्रश्न यह बना कि क्या बुजुर्गों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास बेदखली का आदेश देने की शक्ति है?

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि 2007 का कानून कल्याणकारी कानून है और उसकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाए। धारा 7 के तहत गठित ट्रिब्यूनल और धारा 8 के तहत उसे प्राप्त शक्तियों को सिर्फ कागजी औपचारिकता मानकर नहीं देखा जा सकता। यदि बुजुर्ग की देखभाल, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए किसी बच्चे या रिश्तेदार को संपत्ति से हटाना आवश्यक हो, तो ऐसी राहत दी जा सकती है।

यानी अदालत का संदेश साफ है कि संपत्ति पर अधिकार मालिकाना दस्तावेज का विषय नहीं है; जब उस संपत्ति में रहने वाला वरिष्ठ नागरिक अपने ही बच्चों से असुरक्षित हो जाए, तब कानून का पहला उद्देश्य उसकी सुरक्षा और गरिमा बन जाता है। इसलिए न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए इस दिशा में निर्णय बताते हैं कि बुजुर्गों का हक उनकी अर्जित संपत्ति पर उनके जीवित रहते हुए सदैव ही बना रह सकता है।

इस संबंध में सितंबर 2025 में 'कमलाकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर' मामले को भी देखा जा सकता है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल की बेदखली संबंधी शक्ति को और स्पष्ट किया। लगभग 80 वर्षीय कमलकांत मिश्रा और उनकी 78 वर्षीय पत्नी की संपत्तियों पर उनके बेटे ने कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी ही संपत्तियों में रहने नहीं दिया जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने संपत्ति खाली कराने और माता-पिता को मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को गलत माना और कहा कि कल्याणकारी कानून के तहत ट्रिब्यूनल को ऐसी स्थिति में बच्चे या रिश्तेदार को हटाने की शक्ति हो सकती है।

इसी तरह से यह फैसला मौजूदा निर्णय के कानूनी आधार को समझने में खासा महत्वपूर्ण है। जिसमें कि 'उर्मीला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित' जनवरी 2025 केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण से जुड़े कानून की कल्याणकारी प्रकृति को रेखांकित किया। यदि इन फैसलों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर ओर साफ होती है। न्यायालय अब वरिष्ठ नागरिक कानून को आज सिर्फ आर्थिक भरण-पोषण का कानून नहीं मान रही हैं। इसके केंद्र में बुजुर्ग का सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन है।

भारतीय परिवारों में अक्सर माता-पिता जीवनभर की कमाई से घर बनाते हैं और बाद में बच्चों के नाम संपत्ति कर देते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब संपत्ति हस्तांतरण के बाद वही बच्चे माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक संदेश शायद यही है कि बुजुर्गों की सुरक्षा को पारिवारिक दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। माता-पिता ने बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी लगा दी, इसका अर्थ यह नहीं कि बुढ़ापे में उन्हें उसी घर में अपमान सहने के लिए मजबूर किया जाए।

कानून यहां परिवार को बुजुर्ग को संरक्षण देने के लिए कह रहा है। यहां समझ लें कि अदालत का हस्तक्षेप उस अंतिम दीवार की तरह है, जिसके पीछे एक बुजुर्ग अपने सम्मान के साथ खड़ा हो सकता है और यही इस फैसले का व्यापक अर्थ है। जिस व्यक्ति ने जीवनभर परिवार को घर दिया, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने ही घर में गरिमा से रहने का अधिकार भी कानून सुनिश्चित करता है।

जनजातीय संस्कृति, पहचान और ज्ञान-परंपरा पर प्रभाव

औपनिवेशिक हस्तक्षेप से संवैधानिक संरक्षण तक

डॉ भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

भारत की जनजातीय सभ्यताएं केवल कुछ समुदायों की सामाजिक पहचान नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सभ्यता की बहुलतापूर्ण संरचना, प्रकृति-केंद्रित जीवन-दृष्टि और सामुदायिक ज्ञान-परंपरा की महत्वपूर्ण वाहक हैं। जनजातीय समाजों ने सदियों से जंगल, जल, जमीन, कृषि, औषधीय वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, मौसम, लोककला, संगीत, नृत्य, मौखिक इतिहास और सामुदायिक जीवन के संबंध में ऐसी ज्ञान-परंपराएं विकसित कीं, जिनका संचरण मुख्यतः पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से होता रहा है।

किन्तु औपनिवेशिक शासन, मिशनरी गतिविधियों, बाहरी प्रशासनिक व्यवस्था, वन कानूनों, भूमि संबंधी नीतियों और औपनिवेशिक शिक्षा ने इन समाजों की पारंपरिक संरचनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने इस ऐतिहासिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए।

इसलिए जनजातीय प्रश्न को केवल विकास या पिछड़ेपन के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आधुनिकीकरण और संवैधानिक संरक्षण के बीच जनजातीय समाज अपनी भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, सामुदायिक संस्थाओं और पारंपरिक ज्ञान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है।

औपनिवेशिक हस्तक्षेप और जनजातीय जीवन में परिवर्तन

औपनिवेशिक शासन से पहले अनेक जनजातीय समुदायों में भूमि, जंगल और जल संसाधनों का संबंध केवल आर्थिक स्वामित्व से नहीं, बल्कि सामुदायिक अधिकार, सामाजिक दायित्व और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा था।

ब्रिटिश प्रशासन ने राजस्व, वन प्रबंधन और भूमि स्वामित्व की आधुनिक कानूनी व्यवस्थाओं को लागू किया। वन क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में लेने से जनजातीय समुदायों के पारंपरिक उपयोग-अधिकार प्रभावित हुए। जंगल, जो उनके लिए भोजन, औषधि, ईंधन, आवास और धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन का आधार था, धीरे-धीरे प्रशासनिक और वाणिज्यिक संसाधन के रूप में देखा जाने लगा।

इस परिवर्तन का परिणाम केवल आर्थिक विस्थापन नहीं था। इससे जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं और प्रकृति के साथ उसके संबंध पर भी प्रभाव पड़ा।

मिशनरी गतिविधियां और सांस्कृतिक परिवर्तन

जनजातीय क्षेत्रों में मिशनरी गतिविधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक क्षेत्रों में मिशनरी संस्थाओं ने विद्यालय और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए तथा स्थानीय भाषाओं में साहित्य तैयार किया।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से कई स्थानों पर पारंपरिक विश्वासों, पूजा-पद्धतियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। कुछ समुदायों में धार्मिक पहचान में परिवर्तन आया, जबकि कई स्थानों पर पारंपरिक और नए धार्मिक-सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण भी विकसित हुआ।

इसलिए मिशनरी प्रभाव का मूल्यांकन एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान को स्वीकार करते हुए यह भी अध्ययन आवश्यक है कि धार्मिक परिवर्तन ने जनजातीय पहचान, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक संस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित किया।

औपनिवेशिक शिक्षा और मौखिक ज्ञान-परंपरा

जनजातीय समाजों में ज्ञान का बड़ा हिस्सा पुस्तकों में नहीं, बल्कि लोककथाओं, गीतों, मिथकों, अनुष्ठानों, कृषि-परंपराओं, लोक चिकित्सा और वरिष्ठ पीढ़ी के अनुभवों में सुरक्षित रहा है।

औपनिवेशिक शिक्षा ने ज्ञान को औपचारिक विद्यालय और लिखित पाठ्यक्रम से जोड़ दिया। इससे आधुनिक शिक्षा के अवसर तो बढ़े, लेकिन पारंपरिक ज्ञान के कई रूपों को अवैज्ञानिक या अप्रासंगिक समझे जाने का खतरा भी पैदा हुआ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनजातीय ज्ञान को केवल लोककथा या सांस्कृतिक विरासत मानकर संग्रहालयों में न रखा जाए, बल्कि उसके वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाए।

भाषा पर प्रभाव

भाषा किसी भी समुदाय की पहचान की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। अनेक जनजातीय भाषाएं लंबे समय तक मौखिक परंपरा पर आधारित रहीं। बाहरी प्रशासन, विद्यालयी शिक्षा और रोजगार की आवश्यकताओं ने क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाया।

इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ जनजातीय भाषाओं के प्रयोग का क्षेत्र सीमित हुआ और नई पीढ़ी में मातृभाषा से दूरी बढ़ी।

यह केवल भाषाई परिवर्तन नहीं है। किसी भाषा के कमजोर होने का अर्थ उसके साथ जुड़े लोकगीत, कहावतें, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि ज्ञान, धार्मिक अवधारणाएं और सामुदायिक इतिहास के कमजोर होने का भी खतरा है।

कला, लोक-संस्कृति और धार्मिक विश्वास

जनजातीय चित्रकला, नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, हस्तशिल्प, आभूषण और धार्मिक प्रतीक केवल सौंदर्य की वस्तुएं नहीं हैं। वे सामुदायिक इतिहास और सामूहिक स्मृति के माध्यम हैं।

आधुनिक बाजार ने जनजातीय कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है, लेकिन इसके साथ व्यावसायीकरण की चुनौती भी सामने आई है। यदि कलाकार और समुदाय अपने सांस्कृतिक ज्ञान के अधिकार से वंचित हो जाएं, तो उनकी कला बाजार की वस्तु तो बन सकती है, लेकिन उसके पीछे की सांस्कृतिक आत्मा कमजोर हो सकती है।

इसी प्रकार जनजातीय धार्मिक विश्वासों को समझते समय उन्हें किसी एक बाहरी धार्मिक ढांचे में समाहित करने के बजाय उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भभूमि में समझना आवश्यक है।

भारतीय संविधान और जनजातीय संरक्षण

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने जनजातीय समाजों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक विशेष प्रावधान किए।

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 16(4) राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का आधार देता है।

अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

जनजातीय समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।

अनुच्छेद 243ष्ठ पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन समुदायों की आवाज सुनिश्चित करना है जिनका पारंपरिक जीवन लंबे समय तक बाहरी प्रशासनिक संरचनाओं से प्रभावित रहा।

अनुच्छेद 244 और पांचवीं तथा छठी अनुसूची

जनजातीय प्रशासन की दृष्टि से अनुच्छेद 244 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पांचवीं और छठी अनुसूची की व्यवस्था की गई है।

पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। यह मुख्यतः उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है जहां जनजातीय आबादी और उनकी विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां विशेष संरक्षण की मांग करती हैं।

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था करती है। इसका मूल उद्देश्य स्थानीय परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासनिक स्वायत्तता को संवैधानिक संरक्षण देना है।

अनुच्छेद 275(1) और वित्तीय सहायता

अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध करा सकती है।

यह प्रावधान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जनजातीय विकास को केवल राज्य सरकारों की सामान्य योजनाओं पर निर्भर न रखते हुए केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा सरकार को आवश्यक सुझाव देना है। यह व्यवस्था जनजातीय अधिकारों की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है।

अनुच्छेद 342 और अनुसूचित जनजातियों की पहचान

अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल से परामर्श के बाद, किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संसद को इस सूची में समावेशन या विलोपन करने की शक्ति प्राप्त है।

यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदायों से जुड़ा होता है।

वन अधिकार और सामुदायिक जीवन

जनजातीय समाज और जंगल का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। इसी पृष्ठभूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है, महत्वपूर्ण है।

इस कानून ने व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में ग्रामसभा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया।

यह दृष्टिकोण जनजातीय समाज को केवल वन-निर्भर आबादी मानने के बजाय उसे वन संसाधनों के पारंपरिक संरक्षक और हितधारक के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम–PESA

PESA, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को जनजातीय परंपराओं और ग्रामसभा की भूमिका के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

ग्रामसभा को स्थानीय संसाधनों, सामाजिक प्रथाओं और सामुदायिक हितों से जुड़े विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका देना इसकी प्रमुख विशेषताओं में है।

यहां संविधान की मूल भावना स्पष्ट दिखाई देती है– जनजातीय विकास का अर्थ केवल बाहर से विकास पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को विकास संबंधी निर्णयों का भागीदार बनाना है।

संवैधानिक संरक्षण और वास्तविक चुनौती

भारत का संवैधानिक ढांचा जनजातीय समाज के लिए व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। फिर भी व्यवहार में कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

पहली चुनौती है–कानून और क्रियान्वयन के बीच अंतर।

दूसरी चुनौती है–विकास और विस्थापन का प्रश्न। सड़क, बांध, खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाएं राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन यदि इनके कारण जनजातीय समुदाय अपनी भूमि, जंगल और सांस्कृतिक परिवेश से विस्थापित होता है तो विकास की सामाजिक कीमत का मूल्यांकन आवश्यक है।

तीसरी चुनौती है–भाषाई क्षरण। यदि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ से नहीं जुड़ती तो नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक ज्ञान-व्यवस्था से दूर हो सकती है।

चौथी चुनौती है–सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। जनजातीय समाज को केवल गरीबी, पिछड़ेपन और विकास की कमी के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बदलनी होगी।

आगे की दिशा

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का अर्थ उन्हें आधुनिकता से अलग करना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य ऐसा विकास मॉडल होना चाहिए जिसमें आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार के अवसरों के साथ सांस्कृतिक स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे।

इसके लिए पांच स्तरों पर विशेष प्रयास आवश्यक हैं–

1. जनजातीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा और डिजिटल सामग्री का विकास।

2. पारंपरिक ज्ञान का समुदाय की भागीदारी से दस्तावेजीकरण।

3. जनजातीय कला और हस्तशिल्प के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा।

4. ग्रामसभा और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक भावना के अनुरूप वास्तविक भागीदारी।

5. जनजातीय इतिहास और संस्कृति को भारतीय इतिहास के मुख्य विमर्श में उचित स्थान।

जनजातीय संस्कृति को समझने का सही दृष्टिकोण न तो उसे अतीत की वस्तु मानना है और न ही उसे आधुनिक विकास के रास्ते की बाधा समझना। जनजातीय समाज भारत की बहुलतावादी सभ्यता का जीवंत हिस्सा है।

औपनिवेशिक शासन और उसके बाद के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने जनजातीय भाषाओं, धार्मिक विश्वासों, पारंपरिक संस्थाओं और ज्ञान-परंपराओं को प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत ने संविधान के माध्यम से इस ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया–अनुच्छेद 14, 15, 16, 46, 244, 275, 330, 332, 338, 342 तथा पांचवीं और छठी अनुसूची जैसे प्रावधान इसी संवैधानिक दृष्टि के महत्वपूर्ण आधार हैं।

लेकिन संवैधानिक संरक्षण तभी प्रभावी होगा जब वह जमीन पर अधिकार, भागीदारी, सम्मान और सांस्कृतिक आत्मनिर्णय में परिवर्तित हो।

अंततः जनजातीय विकास का प्रश्न केवल यह नहीं है कि जनजातीय समाज को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की मुख्यधारा जनजातीय समाज की अपनी ज्ञान-परंपराओं, प्रकृति-दृष्टि, सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक विविधता से क्या सीख सकती है।

यही दृष्टिकोण भारत की लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र-व्यवस्था को अधिक मजबूत बना सकता है।

रायपुर : नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस सोनमणि बोरा ने संभाला कार्यभार

रायपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सोनमणि बोरा ने आज बुधवार को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत श्री बोरा को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया गया है। वे प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री बोरा ने विभागीय अधिकारियों से विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों और विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर विभाग के संचालक रिमिजियुस एक्का, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, उप सचिव भागवत जायसवाल, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा, संयुक्त संचालक मिथिलेश अवस्थी, उप संचालक अरुण साहू, सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि तथा अधीक्षण अभियंता रमेश सिंह के साथ ही अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि, श्री बोरा की राज्य गठन के पश्चात रायपुर को राजधानी के रूप में संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे रायपुर नगर पालिक निगम, आरडीए, बीडीए के आयुक्त एवं सीईओ रहे। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव से रायपुर और बिलासपुर के नगर विकास के साथ-साथ कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बिलासपुर जैसे जिलों के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

तस्वीरों में उतरा छत्तीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान

रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

रायपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बुधवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट 'दृश्य संवाद 2026' का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की 'प्रकृति एवं पर्यावरण' कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं 'संस्कृति एवं परंपरा' कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। 'समाचार एवं जनसरोकार' कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं।

फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम : श्याम बिहारी जायसवाल : प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तय करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए।

उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।

तस्वीर पत्रकारिता की अधूरी खबर को पूरा करती है : मोहन तिवारी : रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'दृश्य संवाद' केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, फोटो जर्नलिस्ट साथियों के बिना अधूरी है। खबर को जीवंतता और प्रभाव देने में एक तस्वीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने कहा कि एक सशक्त तस्वीर के लिए कई बार लंबे कैप्शन की जरूरत नहीं होती। बिना किसी कैप्शन के भी तस्वीर अपने आप में पूरी खबर कहने की ताकत रखती है। फोटो जर्नलिस्ट जिस क्षण को कैमरे में कैद करता है, वह आने वाले समय में उस घटना का दस्तावेज बन जाता है।

बांगो बांध से दो जलद्वार बंद, अब सात गेट से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी

कोरबा 19 अगस्त (हि.स.)। मिनीमाता हसदेव बांगो बांध में पानी की आवक कम होने के कारण जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। स्थिति को देखते हुए उच्चाधिकारियों से चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार बांध के दो जलद्वार बंद किए गए हैं। अब कुल 7 जलद्वारों के माध्यम से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. भारती ने बताया कि आज बुधवार को शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच बांध में पानी की आवक कम होने के कारण पिछले तीन घंटे में जलस्तर में करीब 3 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। बांध के जलभराव को नियंत्रित करने के लिए जलद्वारों की कुल ओपनिंग 6.00 मीटर से घटाकर 5.00 मीटर कर दी गई है।

वर्तमान में बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी 7 जलद्वारों एवं पावर हाउस के माध्यम से की जा रही है। शाम 7:30 बजे की स्थिति में बांध का जलस्तर 358.24 मीटर (91.54 प्रतिशत) दर्ज किया गया। बांध में पानी का इनफ्लो 23,732 क्यूसेक तथा आउटफ्लो 35,807 क्यूसेक है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के जलस्तर, पानी की आवक एवं निकासी की सतत निगरानी की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुसार जलद्वारों के संचालन का निर्णय लिया जा रहा है। इसी तरह दर्री बांध के 4 गेट खोले गए हैं

जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल जी की अध्यक्षता में गठित समिति की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में 21 अगस्त को होगी कृषि यंत्रों की ई-लाटरी

कृषि यंत्रों के टोकन कन्फर्म कराने के लिए 21 अगस्त को होगी ई-लाटरी, कृषक बंधु ससमय करें प्रतिभाग

आगरा. 19.08.2026/उप निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार ने जनपद आगरा के समस्त कृषक बन्धुओं को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2026×27 में कृषि विभाग मंशानुरुप संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिन कृषकों द्वारा दिनांक-16-07-2026 से 10-08-2026 तक कृषि यंत्रों की विभागीय पोर्टल पर बुकिंग की गयी है तथा लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने के कारण जिन कृषकों के टोकन कन्फर्म नहीं हुए हैं ऐसे कृषकों के टोकन को कन्फर्म करने हेतु शासन द्वारा ई-लाटरी कराये जाने का प्रावधान है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति की उपस्थिति में दिनांक-21-08-2026 को अपरान्ह-12:30 बजे से विकास भवन सभागार, संजय पैलेस, आगरा में ई-लाटरी की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जिन कृषक बन्धुओं ने कृषि विभाग मंशानुरुप संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों की बुकिंग की है वह कृषक बन्धु ई-लाटरी प्रकिया में दिनांक-21-08-2026 को अपरान्ह-12:30 बजे स्थान- विकास भवन सभागार संजय पैलेस, आगरा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

अगस्त माह के राशन वितरण की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई गई, अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

ई-पॉस, ओटीपी और पोर्टेबिलिटी से 25 अगस्त तक राशन प्राप्त करने की मिलेगी सुविधा

आगरा. 19.08.2026/जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह-अगस्त, 2026 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) का निःशुल्क वितरण कराया जाना दिनांक 05.08.2026 से 18.08.2026 तक निर्धारित किया गया है। दिनांक 03.08.2026 से 11.08.2026 तक कॉवड़ यात्रा के कारण कतिपय जनपदों में खाद्यान्न का उठान एवं वितरण का कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो सका है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त के दृष्टिगत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने हेतु माह-अगस्त, 2026 के सापेक्ष खाद्य वितरण की तिथि दिनांक 25.08.2026 तक विस्तारित की गयी है। दिनांक 25.08.2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 18.08.2026 के साथ दिनांक 25.08. 2026 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 25.08.2026 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।

सैंपऊ नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक एकजुट होकर वार्ड स्तर पर जीत के लिए संकल्प लिया

धौलपुर (निज संवाददाता) । सैंपऊ नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैंपऊ पर आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला महासचिव एवं प्रभारी सैंपऊ रोशनी शिवहरे प्रभारी केशव चंद्र मीणा बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा सैंपऊ ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा एवं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों को मजबूती से रखने तथा संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई बैठक में सभी टिकट के इच्छुक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट स्वर में संकल्प लिया कि सैंपऊ नगर पालिका में ईमानदार पारदर्शी जनसेवा को समर्पित और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने वाला कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया जाएगा। बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत के लिए पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ मैदान में उतरने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बरसात में हादसों के चलते धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दमोह झरने पर 18 अगस्त से 30 सितंबर तक लगाया प्रवेश प्रतिबंध

धौलपुर (निज संवाददाता)। बरसात के मौसम में दमोह झरने पर बढ़ते पर्यटक आवागमन तथा पानी में डूबने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर उपखंड सरमथुरा स्थित दमोह झरने एवं उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों एवं पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। प्राय देखने में आया है कि बरसात के दौरान दमोह झरने को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक एवं आमजन पहुंचते हैं। झरने में पानी का बहाव बढ़ने के कारण पूर्व में पानी में डूबने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं,जिससे जनजीवन एवं लोक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग झरने के आसपास पहुंचते हैं जिससे जनहानि एवं गंभीर चोट की संभावना बनी रहती है। इस आदेश के तहत दमोह झरने तथा उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों एवं पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 18 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने आमजन एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

आत्मा बैठक में नवाचारी खेती पर जोर प्रशिक्षण का परिणाम आकलन अनिवार्य

धौलपुर । कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) की शासी परिषद की बैठक का अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन किया गया। बैठक में आत्मा के तहत चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने पर चर्चा हुई। उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रसार पर जोर दिया गया तथा विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचाने के उपायों पर मंथन किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने गत वर्ष के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की समीक्षा करते हुए उपलब्धियों का आकलन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि आत्मा के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आउटकम असेसमेंट हो। किसान परिभ्रमण कार्यक्रमों का भी परिणाम मूल्यांकन हो। प्रशिक्षण से किसानों को कितना व्यावहारिक लाभ मिला, आय में कितना बदलाव आया तथा कृषि उत्पादन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया इसके लिए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रशिक्षण की नई रूपरेखा तय करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य फसलों के प्रशिक्षण राज्य के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में ही किए जाए विशिष्ट खेती, नवाचारी पद्धतियों के प्रशिक्षण राज्य के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में किए जाएं।

बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कृषि विकास को गति देने तथा किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों सहित जिले के कृषक उपस्थित रहे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की हुई घोषणा

घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता हुई लागू जिले में दो चरणों में होगा मतदान

धौलपुर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव के अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न कराए जाएगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1 सितम्बर अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 3 सितम्बर को दोपहर 3 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितम्बर मतदान की तिथि प्रथम चरण के लिए 9 सितम्बर व द्वितीय चरण के लिए 11 सितम्बर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतगणना की तिथि 14 सितम्बर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अध्यक्ष पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितम्बर नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 17 सितम्बर अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 18 सितम्बर अपरान्ह 3 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितम्बर मतदान की तिथि एवं समय 21 सितम्बर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतगणना की तिथि एवं समय 21 सितम्बर को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की तिथि 22 सितम्बर निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक का प्रारंभ प्रातः 10 बजे नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी का समय अपरान्ह 2 बजे तक मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2.30 बजे से 5 बजे तक इसके पश्चात मतगणना की जाएगी। जिले में दो चरणों में होगा मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद धौलपुर के 60 वार्ड नगर पालिका राजाखेड़ा के 35 वार्ड नगर पालिका मनिया के 20 वार्ड एवं नगर पालिका सैपऊ के 20 वार्ड का प्रथम चरण 9 सितम्बर को तथा नगर पालिका बसेड़ी के 25 वार्ड, नगर पालिका बाड़ी के 45 वार्ड एवं नगर पालिका सरमथुरा के 25 वार्ड का द्वितीय चरण 11 सितम्बर को मतदान किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके है। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण/मनरेगा कार्ड बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज शामिल है। इन 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से वे ही दस्तावेज मान्य होगें जो नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हो। मतदान सहायता केन्द्र किए जाएगे स्थापित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित कर इन सहायता केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों के स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएगें। अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगी चुनाव खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग कटआउटों होर्डिंग्स पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए आयोग द्वारा प्रतिबंध किए है। नगर परिषद पार्षद के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये एवं नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है।आदर्श आचरण संहिता रहेगी लागू राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है। जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। सम्बन्धित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगें। नई स्कीम नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फील्ड स्टाफ का वर्चुअल ओरियंटेशन

एपीएच और पीपीएच के प्रबंधन पर रहा विशेष जोर

धौलपुर, 19 अगस्त। जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से फील्ड स्टाफ का वर्चुअल माध्यम से ओरियंटेशन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा के निर्देश पर आयोजित इस ओरियंटेशन में विशेष रूप से एंटेपार्टम हैमरेज(एपीएच) अर्थात 20 या 24 सप्ताह के बाद से लेकर बच्चे के जन्म से पहले तक योनि से होने वाला रक्तस्राव। तथा पोस्ट पार्टम हेमरेज (पीपीएच), अर्थात प्रसवोत्तर रक्तस्राव की समय पर पहचान, प्राथमिक प्रबंधन एवं रेफरल व्यवस्था को लेकर फील्ड स्टाफ को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

ओरियंटेशन के दौरान जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला रक्तस्राव से मातृ एवं भ्रूण दोनों के लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। फील्ड स्तर पर गर्भवती महिला में किसी भी प्रकार के असामान्य योनि रक्तस्राव को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में देरी न करते हुए महिला की स्थिति का प्राथमिक आकलन, आवश्यक जीवनरक्षक उपाय तथा समय पर उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफरल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इसी प्रकार प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव यानी पीपीएच ''को मातृ मृत्यु के प्रमुख रोकथाम योग्य कारणों में से एक बताते हुए इसके ''समय पर पहचान एवं त्वरित प्रबंधन की जानकारी दी गई। फील्ड स्टाफ को प्रसव के बाद महिला की लगातार निगरानी, अत्यधिक रक्तस्राव के संकेतों की पहचान, रक्तचाप एवं नाड़ी सहित आवश्यक जीवन संकेतों की निगरानी तथा स्थिति गंभीर होने पर बिना विलंब उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में रेफर करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान सीनियर रेजिडेंट डॉ अनन्या ने कहा कि पीपीएच की स्थिति में पहले कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रसव के बाद महिला की निगरानी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल उपचार शुरू करने, आवश्यक दवाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जरूरत पड़ने पर रक्त एवं रक्त घटकों की व्यवस्था के लिए संबंधित संस्थान एवं ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान, गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच, एनीमिया की पहचान एवं प्रबंधन, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए केवल स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर उपचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि फील्ड स्तर पर खतरे के संकेतों की समय पर पहचान और त्वरित रेफरल बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला अथवा प्रसूता में रक्तस्राव जैसे गंभीर लक्षण सामने आने पर परिवार को भी स्थिति की गंभीरता समझाते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।

ओरियंटेशन के दौरान फील्ड स्टाफ को यह भी निर्देश दिए गए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का नियमित फॉलोअप किया जाए, प्रसव के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान की पूर्व योजना बनाई जाए तथा आपात स्थिति में रेफरल के दौरान आवश्यक समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि उपचार में किसी प्रकार की देरी न हो। इस वर्चुअल ओरियंटेशन में जेपाईगो एसपीओ प्रभु, डीपीओ शशांक वशिष्ठ एवं प्रोग्राम ऑफिसर सुमित पुरी मौजूद रहे।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केन्द्र, बिचपुरी के सभागार में किसान दिवस का हुआ आयोजन

किसान दिवस में 12 शिकायतों का जिलास्तरीय अधिकारियों ने किया समाधान, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

कृषि यंत्रीकरण, फार्मर रजिस्ट्री और फसल बीमा योजनाओं तथा लम्पी स्किन डिजीज से बचाव और फसली ऋण की किसानों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

किसान दिवस में करीब 100 किसानों ने लिया भाग, अधिकारियों ने समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया भरोसा

आगरा. 19.08.2026/अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) श्री जुबेर बेग की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केन्द्र, बिचपुरी, आगरा के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद आगरा के किसानों की समस्याओं का जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। जिसमें सहकारिता विभाग से सम्बन्धित 03, सिचाई विभाग से सम्बन्धित 02, विद्युत विभाग से सम्बन्धित 01, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से सम्बन्धित 02, उद्यान विभाग से सम्बन्धित 02, मण्डी समिति से सम्बन्धित 01, उप कृषि निदेशक से सम्बन्धित 01, कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई। अपर जिलाधिकारी अधिकारी, महोदय, (नमामि गंगे) आगरा ने किसान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उप कृषि निदेशक, आगरा ने ई0 लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के सम्बन्ध में, एवं फार्मर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में किसान दिवस में उपस्थित कृषकों को अवगत कराया गया। जिला कृषि अधिकारी, आगरा ने फसल बीमा से खेती में होने वाले लाभों के वारे में अवगत कराया गया। डा0 व्रजेश यादव (प्रतिनिधि) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा, ने पशुओं में होने वाले लम्पी स्किन डिजीज के बचाव के बारे में जानकारी दी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा, ने अपने विभाग से मिलने वाले फसली ऋण के वारे में अवगत कराया। अपर जिलाधिकारी अधिकारी, महोदय, (नमामि गंगे) ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

किसान दिवस उप कृषि निदेशक, आगरा, जिला कृषि अधिकारी, आगरा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा (प्रतिनिधि), आगरा, जिला उद्यान अधिकारी, आगरा, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, आगरा, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विद्युत, आगरा, अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, आगरा, अधिशासी अभियन्ता सिचाई नहर, आगरा (प्रतिनिधि), सहायक निदेशक, मत्स्य आगरा, सहायक अभियन्ता (लघु सिचाई) आगरा, जिला खाद विपणन अधिकारी, आगरा आदि जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ ही किसान श्री राजवीर लवानियाँ, एवं श्याम सिंह चाहर, लक्ष्मी नरायण बघेल, श्री सोमवीर यादव, लाखन सिंह, पुष्पेन्द्र जैन, आदि लगभग 100 किसान भी सभागार में उपस्थित रहे।

मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने किया निरीक्षण

आगरा (निज संवाददाता)। मंडल रेल प्रबंधक, आगरा श्री गगन गोयल के निर्देशन में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, आगरा मंडल श्री अंकित गुप्ता द्वारा आज मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान श्री अंकित गुप्ता ने स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पे एंड यूज़ शौचालय, खानपान स्टॉल/यूनिट, विश्रामालय सहित अन्य यात्री सुविधाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई का अवलोकन किया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वच्छता बनाए रखने तथा खानपान एवं अन्य सेवाओं में निर्धारित दरों एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के क्रम में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अंकित गुप्ता ने मथुरा जंक्शन स्टेशन के स्टेशन निदेशक श्री सुनील शर्मा एवं वाणिज्य सुपरवाइजरों के साथ बैठक भी की। बैठक में स्टेशन पर वाणिज्यिक गतिविधियों एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई तथा यात्रियों की सुविधा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

श्री अंकित गुप्ता ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं के प्रति सजग रहते हुए यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने तथा रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं एवं खानपान इकाइयों में साफ-सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को स्टेशन परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने तथा यात्रियों को स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं!

संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य पर रुपये मांगने के आरोप, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

विजयपुर। संदीपनी विद्यालय विजयपुर में पदस्थ प्राचार्य अजय समाधिया के खिलाफ रुपये मांगने के आरोपों को लेकर की गई शिकायत अब प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की स्थिति को लेकर सवालों के घेरे में है। शिकायत सामने आने के बाद मामले को मीडिया द्वारा भी प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन शिकायत के कई दिन बाद भी संबंधित विभाग की ओर से जांच की प्रगति अथवा कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शैक्षणिक संस्था से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारी के खिलाफ आर्थिक लेन-देन से संबंधित शिकायत सामने आने पर निष्पक्ष जांच और तथ्यों की स्पष्टता जरूरी है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिकायत पर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई और जांच वर्तमान में किस स्तर पर है।

शिकायत हुई, खबर भी चली... फिर कार्रवाई कहां अटकी? प्राचार्य के खिलाफ रुपये मांगने के आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित स्तर पर शिकायत किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद मामला मीडिया में भी आया। ऐसे में उम्मीद थी कि संबंधित विभाग शिकायत के तथ्यों की जांच करेगा, शिकायतकर्ता और संबंधित प्राचार्य का पक्ष सुनेगा तथा दस्तावेजों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगा।हालांकि, अभी तक जांच की प्रगति या किसी निर्णय की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत अथवा आरोप मात्र से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। आरोपों की सत्यता का निर्धारण निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है। यदि शिकायत सही है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित व्यक्ति की स्थिति भी आधिकारिक रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए।

प्रशासन की चुप्पी से बढ़ रहे सवाल

मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि शिकायत पर जांच शुरू हुई या नहीं? यदि जांच शुरू हो चुकी है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या शिकायतकर्ता और प्राचार्य से उनके बयान लिए गए हैं? क्या किसी अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या जांच रिपोर्ट तैयार हुई है? यदि जांच अभी लंबित है तो इसकी वजह क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या समयसीमा निर्धारित की गई है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग की ओर से सामने आना जरूरी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले में पारदर्शी तरीके से जांच कर वास्तविक तथ्य सामने लाए जाने चाहिए। इससे शिकायतकर्ता को भी स्थिति स्पष्ट होगी और संबंधित प्राचार्य को भी अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलेगा।

अब विभाग के आधिकारिक जवाब का इंतजार

शिकायत के बाद मीडिया में मामला उठने के बावजूद यदि विभाग की ओर से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल उठते हैं। अब निगाह संबंधित विभाग पर है कि वह मामले में जांच की स्थिति सार्वजनिक करता है या नहीं। यदि जांच लंबित है तो उसका कारण क्या है, शिकायतकर्ता को अब तक क्या जानकारी दी गई और मामले में आगे की कार्रवाई कब तक पूरी होगी–इन सभी सवालों पर विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

फिलहाल सवाल सिर्फ शिकायत का नहीं, बल्कि शिकायत पर हुई कार्रवाई का है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब तक मामले की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखता है।

श्योपुर में विकास कार्यों को लेकर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर सख्त

PM जनमन और PMGSY के तहत 105 सड़कों की टेंडर प्रक्रिया जारी, दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने पर जोर–सांसद बोले, समयसीमा में पूरे हों निर्माण कार्य

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले में सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े निर्माण कार्यों को गति देने के लिए क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।

बैठक में कलेक्टर शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी, सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

PM जनमन और PMGSY से गांवों को मिलेगी सड़क कनेक्टिविटी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने बताया कि पीएम जनमन तथा पीएमजीएसवाय के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में सड़कों की टेंडर प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे गांव और बस्तियां जहां कम दूरी की सड़क बनाकर उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है, वहां एप्रोच रोड के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

इसमें विजरपुर से किलोरच रोड, मेवाड़ा माली बस्ती से कैनाल रोड तथा राडेप से लाथ तक सड़क को शामिल करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि इन प्रस्तावों को स्वीकृत कराने के लिए आवश्यक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

'काम लटकना नहीं चाहिए, लंबित कार्यों की सूची मुझे दें'

समीक्षा बैठक में सांसद ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा कराया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे विकास कार्य जो वरिष्ठ स्तर पर स्वीकृति या अन्य कारणों से लंबित हैं, उनकी अलग सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए वरिष्ठ स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जा सकें।

सांसद ने विशेष रूप से सांदीपनि श्योपुर एवं विजयपुर से संबंधित निर्माण कार्यों को आगामी दो माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने भी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश कलेक्टर शीला दाहिमा ने एनएच, पीएमजीएसवाय, आरईएस, स्वास्थ्य विभाग, पीआईयू और लोक निर्माण विभाग सहित पीएम जनमन के तहत संचालित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ कराने के लिए जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भूमिपूजन कराया जाए और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके लोकार्पण की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने 20 अगस्त से आयोजित होने वाले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा के संबंध में भी जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी।

125 दिन रोजगार की गारंटी वाली योजना की भी दी जानकारी

बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सौम्या आनंद ने वीबी-जी रामजी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 125 दिवस के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि योजना में चार प्रमुख श्रेणियों के तहत कुल 313 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं।

इनमें—

107 प्रकार के जल सुरक्षा संबंधी कार्य

90 प्रकार के कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य

86 प्रकार के ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्य

35 प्रकार के आपदा राहत संबंधी कार्य

शामिल किए गए हैं।

150 बेड का अस्पताल लगभग तैयार, एक माह में बिजली सहित शेष काम पूरा करने का दावा

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम प्रबंधक हेमंत रावत ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन 150 बेड का अस्पताल लगभग पूर्ण हो चुका है। भवन में 50 बेड की क्रिटिकल विंग और 100 बेड के जनरल वार्ड की सुविधाएं विकसित की गई हैं।

बताया गया कि अस्पताल से जुड़े बिजली सहित अन्य शेष कार्यों को लगभग एक माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही ढोढर में निर्माणाधीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति की जानकारी भी बैठक में दी गई।

सड़क निर्माण पर करोड़ों का दांव

पीएमजीएसवाय के अधिकारियों ने बैठक में सड़क निर्माण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीएमजीएसवाय-4 और पीएम जनमन के तहत बड़ी संख्या में सड़कों की टेंडर प्रक्रिया भोपाल स्तर पर चल रही है।

अधिकारियों के अनुसार–

पीएमजीएसवाय के तहत करीब 62 करोड़ 18 लाख 7 हजार रुपये की लागत से सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जबकि पीएम जनमन के तहत करीब 72 करोड़ 61 लाख 58 हजार रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी।

इस तरह ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों में करोड़ों रुपये की राशि खर्च की जानी है।

सवाल सिर्फ सड़क बनाने का नहीं, गुणवत्ता और समयसीमा का भी

जिले में करोड़ों रुपये की लागत से सड़क और अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती इन कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने की होगी।

सड़क निर्माण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और कार्यों की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे।

बैठक का स्पष्ट संदेश यही रहा–स्वीकृतियां और बजट तभी सार्थक होंगे, जब सड़क से लेकर अस्पताल तक विकास कार्य समय पर जमीन पर दिखाई दें।

राधा-कृष्ण किरार मन्दिर में भागवत कथा में सजी गोवर्धन लीला की झांकी

भिण्ड (निज संवाददाता)। शहर के प्रसिद्ध राधा-कृष्ण किरार मन्दिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास स्वामी आशीषानंद महाराज ने गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनाकर भक्तों को भक्ति रस का रसपान कराया।

महाराज ने कथा के दौरान बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर ब्रज वासियों की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि यह लीला हमें प्रकृति की पूजा और अहंकार त्याग का संदेश देती है। कथा पण्डाल में गोवर्धन पर्वत की मनोहारी झांकी सजाई गई, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और 'गिरिराज धरण की जय' के जयकारों से पूरा मन्दिर परिसर गूंज उठा।

धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश

स्वामी आशीषानंद महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को धर्म, कर्म और संस्कारों के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मनुष्य भौतिक सुखों में उलझकर अपने धर्म को भूलता जा रहा है। भागवत हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म सेवा, सत्य और प्रेम में है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि व्यक्ति नियम और संयम से जीवन जिए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कथा के दौरान मन्दिर परिसर में भजन-कीर्तन का दौर भी चला। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कथा सुनने पहुंचे। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। सात दिवसीय इस भागवत कथा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु धर्मलाभ ले रहे हैं।

पांच हजार के इनामी बदमाश आलमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर की धमाकेदार कार्रवाई

भिण्ड (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, एएसपी प्रदीप पटेल के निर्देशन एवं लहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आलमपुर पुलिस ने तीन साल से फरार 5 हजार रुपए के इनामी बदमाश को मां बराही देवी मन्दिर से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार आलमपुर थाने में फरियादी ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ बंदूक व लाठियां से जान से मारने की शिकायत दर्ज की कराई थी, जिसको देखते हुए आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पांच हजार का इनाम घोषित किया गया था। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फरारी इनामी बदमाश मां बराही देवी मन्दिर के पास खड़ा है, जिसे आलमपुर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर, एएसआई ओमकार सिंह तोमर, संतोष कुमार, भागवत सरिया, योगेन्द्र शर्मा, शैलेन्द्र शुक्ला, सिद्धांत कौरव, मंगल सिंह, अनिल बघेल, कन्हैया लाल, हुकुम सिंह, अनुराग छारी की सराहनीय भूमिका रही।

औषधि निरीक्षक दल ने मिहोना में मेडिकल स्टोरों का किया औचक निरीक्षण

-औषधियों के नमूने लेकर शा. औषधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे

भिण्ड (निज संवाददाता)। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र के निर्देश पर गठित औषधि निरीक्षकों के दल में भिण्ड रवि कुमार जाटव, दतिया उमेश रामचंदानी एवं अशोकनगर जितेन्द्र शर्मा ने सीएमएचओ डॉ. जेएस यादव के मार्गदर्शन में गत दिवस मिहोना तहसील में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण में चौधरी मेडिकल स्टोर पर मेडिकल के संचालन संबंधी दस्तावेज एवं औषधियों के क्रय विक्रय रिकार्ड्स मौके पर नहीं पाए जाने पर दल द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार जांच कर औषधियों को अपने अधिपत्य में लिए जाने की कार्रवाई की गई एवं प्रकरण को न्यायालय भिण्ड के संज्ञान में लाया गया है।

निरीक्षण के दौरान कुछ औषधियों के नमूने लेकर शा. औषधि प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच एवं विश्लेषण के उद्देश्य से प्रेषित किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर मौक पर बंद पाया गया, जिसमें मेडिकल के संचालक को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। दल के सदस्यों ने बताया कि जिले में आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा एवं मेडिकल का नियमानुसार संचालन नहीं मिलने पर औषधि एवं प्रसारण सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड लोकजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संत रविदास की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा का आयोजन

- आज से 10 सितंबर तक आयोजित की जाएगी रथ यात्रा

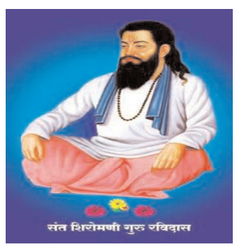

भिण्ड (निज संवाददाता)। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर 'गुरू रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा' अंतर्गत संत शिरोमणि गुरू रविदास आश्रम मण्डी प्रांगण मेहगांव में 20 अगस्त को कलश बंधन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात 10 सितंबर तक पावन कलश रथ में स्थानीय रविदास मन्दिर एवं ग्राम स्तर तक रथ यात्रा प्रारंभ की जाएगी। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन तथा उनके समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से गुरू रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा का आयोजन किया जाना है। उक्त रथ यात्रा 20 अगस्त को भिण्ड से मेहगांव तक निकलेगी,जिसका पड़ाव मेला ग्राउण्ड मेहगांव, 21 अगस्त को मेहगांव से गोहद तक पड़ाव शा. जूनियर बालक छात्रावास गोहद, 22 अगस्त को गोहद से मालनपुर तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास मालनपुर, 23 अगस्त को मालनपुर से गोहद तक वापसी पड़ाव शा. जूनियर बालक छात्रावास चितौरा, 24 अगस्त को चितौरा से मौ तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास मौ, 25 अगस्त को मौ से अमायन तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास अमायन, 27 अगस्त को अमायन से लहार तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास लहार, एक सितंबर को लहार से दबोह तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास दबोह, 2 सितंबर को दबोह से आलमपुर तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास आलमपुर, 3 सितंबर को आलमपुर से लहार तक वापसी पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास लहार, 7 सितंबर को लहार से रौन तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास रौन, 8 सितंबर को रौन से ऊमरी तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास ऊमरी, 9 सितंबर को ऊमरी से भिण्ड तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास भिण्ड, 10 सितंबर को भिण्ड से अटेर तक पड़ाव शा. सीनियर बालक छात्रावास अटेर में किया जाएगा।

सड़क हादसों को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भिण्ड (निज संवाददाता)। ग्वालियर-भिण्ड-इटावा हाईवे-719 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों और जिले में किसानों के सामने खड़े खाद संकट को लेकर भिण्ड महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शांति कुशवाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और इन दोनों गंभीर समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान एनएच-719 की स्थिति और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट कराया गया। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि हाईवे पर दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) की तत्काल पहचान की जाए। साथ ही, आमजन की जान सुरक्षित रखने के लिए सड़क सुधार, दिशा-सूचक बोर्ड (संकेतक) लगाने और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएं, ताकि हादसों के इस सिलसिले पर रोक लग सके। सड़क दुर्घटनाओं के अलावा जिले के अन्नदाताओं की पीड़ा को भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। वर्तमान में रबी की फसल की बुवाई के समय किसानों को खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन से मांग की गई है कि सोसायटियों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए और वितरण प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी व सुचारू बनाया जाए।

इस अवसर पर शांति कुशवाह ने कहा कि आम जनता और किसानों की समस्याओं को लेकर महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जनता के हितों और किसानों के अधिकारों के लिए संगठन आगे भी पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाता रहेगा। ज्ञापन सौंपते समय महिला कांग्रेस की अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं।

मेहदौली में हनुमान मन्दिर परिसर में धसी जमीन, निकली रहस्यमयी गुफा

मेहगांव (निज संवाददाता)। ग्राम मेहदोली क्षेत्र के प्रसिद्ध एवं प्राचीन खेरापति हनुमान मन्दिर परिसर में बीते सप्ताह अचानक जमीन धसने से एक रहस्यमयी गुफा नुमा गड्ढा सामने आया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में कौतूहल और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है।

दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

खबर फैलते ही आस-पास के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु इस अजूबे को देखने के लिए मन्दिर परिसर में एकत्र हो रहे हैं। आस्था और जनश्रुति का केन्द्र स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालु इसे भगवान हनुमान का अलौकिक चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। वहीं गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक सुरंग है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं के अनुसार, बुजुर्गों का दावा है कि यह सुरंग पास के गांव सीताराम की लावन स्थित प्रसिद्ध सीताराम मन्दिर तक जाती है। पुरानी कथाओं और किंवदंतियों का हवाला देते हुए ग्रामीण आज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह वही प्राचीन गुप्त मार्ग हो सकती है, जिसकी चर्चा पूर्वज किया करते थे।

सुरक्षा को लेकर चिंता, प्रशासन से जांच की मांग फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से गुफा के अंदर कोई नहीं गया है। हालांकि, इस घटना से सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा पहलू भी सामने आया है। जिस स्थान पर जमीन धसी है, ठीक उसी के समीप श्रीराम जानकी मन्दिर की ऊंची दीवार स्थित है। गड्ढे के कारण मन्दिर की बुनियाद को खतरा होने की संभावना जताई जा रही है। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल गुफा वाले स्थान को सुरक्षित (बैरीकेडिंग) करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने शासन से गुहार लगाई है कि पुरातत्व विभाग और भू-वैज्ञानिकों की टीम को मौके पर भेजकर इसकी गहन जांच करवाई जाए, ताकि इस रहस्यमयी गुफा का ऐतिहासिक सच सामने आ सके और किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके।

भरौली थाने की कमान नवागत टीआई राय ने संभाली, चार्ज संभालते ही दिए कड़े संकेत

- दीपेन्द्र बोहरे -

भिण्ड। भरौली थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से नवागत थाना प्रभारी अभिषेक राय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही नवागत टीआई ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है।

पदभार ग्रहण करने के बाद टीआई अभिषेक राय ने थाने के समस्त स्टाफ के साथ बैठक की और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व संवेदनशील बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

नवागत टीआई की प्रमुख प्राथमिकताएं

अपराध और अवैध धंधों पर नकेलः सट्टा, जुआ, अवैध शराब और अवैध उत्खनन जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आमजन के लिए खुले रहेंगे द्वारः थाने आने वाले प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी।

महिला व बाल सुरक्षाः महिला सुरक्षा और बाल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

गश्त व्यवस्था में कसावटः रात्रि गश्त और चेकिंग अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

संगठन की मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है : अहिरवार

- कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित

भिण्ड (निज संवाददाता)। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा चौधरी प्रमोद गार्डन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मप्र कांग्रेस कमेटी अजा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यमंत्री दर्जा प्रदीप अहिरवार ने कार्यकर्ताओं को वर्ष 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए तथा कांग्रेस की नीतियों एवं अजा समाज के अधिकारों और सम्मान की आवाज को मजबूती से उठाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर दलित समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अजा समाज के साथ-साथ पिछड़े एवं सवर्ण समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई भी मजबूती से लड़ती रहेगी । उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

अटेर विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज ने हमेशा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी समाज के अधिकार,सम्मान और समान अवसर के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें संगठन के माध्यम से मजबूती से उठाएं। सम्मेलन को अजा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भिण्ड दतिया प्रभारी कुलदीप मगरैया, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णगोपाल चौरसिया, शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया पिंकी, अजा विभाग ग्रामीण जिलाध्यक्ष रूपसिंह खन्ना, नरोत्तम सिंह नरवरिया आदि ने संबोधित किया। संचालन अजा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भिण्ड-दतिया प्रभारी कुलदीप मगरैया ने एवं आनंद शाक्य ने आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, अरविन्द यादव हैवदपुरा, ब्लॉक अध्यक्ष अटेर सुनील शर्मा सोनू, बलराम जाटव, सरोज वाल्मीकि, मायाराम जाटव, देवेन्द्र पाठक, सुमित त्रिवेदिया, आनंद शाक्य, डीपी खन्ना, डॉ. अमर सिंह जाटव, अभिषेक मौर्य, राजेन्द्र परिहार आदि मंचासीन रहे एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक कुशवाह ने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मुख्यमंत्री से की चर्चा

- मेडिकल कॉलेज, गौरी सरोवर के विकास एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया

भिण्ड (निज संवाददाता)। भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट कर क्षेत्रीय विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र की प्रगति, जन आकांक्षाओं एवं विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव एवं विचार साझा किए। प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से निरंतर प्रेरणा मिलती है।

विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भिण्ड के विकास, सरकारी योजनाओं को समाज की अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही मेडिकल कॉलेज एवं गौरी सरोवर के विकास के लिए तथा शहरी एवं ग्रामीण अंचल में अनेक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया। विधायक ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर आने वाले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।

12 साल से फरार 10 हजार का इनामी स्थाई वारंटी गिरफ्तार

भिण्ड (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक भिण्ड सूरज कुमार वर्मा, एएसपी प्रदीप पटेल के निर्देशन एवं सीएसपी निरंजन सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देहात शिवप्रताप सिंह राजावत के नेतृत्व में इनामी व स्थाई वारंटियों की धरपकड़ हेतु टीम गठित की गई। अभियान के तहत देहात थाना पुलिस को 12 वर्ष से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वारंटी के विरूद्ध वर्ष 2013 में थाना देहात में अपराध क्र.286/2013 धारा 279, 337, 338 भादंवि का मामला पंजीबद्ध किया था। मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी पिछले 12 वर्ष से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल कर तथा अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था। पुलिस की सतत निगरानी व मुखबिर तंत्र की सक्रियता के चलते उक्त वारंटी को बुधवार को सुभाष तिराह भिण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक शिवप्रताप सिंह राजावत, उपनिरीक्षक धर्मसिंह तोमर, प्रधान आरक्षक नीरज सिंह, आरक्षक भूपेन्द्र तोमर, सुमित शर्मा, अतुल पाण्डेय, अवधेश चौहान, फिरोज खान, दीपक जादौन, आदित्य चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आवश्यक सूचना

रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झाँसी मंडल के बीना–वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी खंड में आगासोद–बीना के मध्य तीसरी लाइन के निर्माण के संबंध में आगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन, रिशेड्यूलिंग एवं रेग्युलेशन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
64618	ललितपुर-बीना	27.09.2026 से 15.10.2026
64617	बीना-ललितपुर	27.09.2026 से 15.10.2026
12192	जबलपुर-हज़रत निज़ामुद्दीन	26.09.2026 से 14.10.2026
12191	हज़रत निज़ामुद्दीन-जबलपुर	27.09.2026 से 15.10.2026
05073	क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेगलूरु-लालकुआँ	29.09.2026, 06.10.2026, 13.10.2026
05074	लालकुआँ-क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेगलूरु	26.09.2026, 03.10.2026, 10.10.2026
22163	भोपाल-खजुराहो	15.10.2026
22164	खजुराहो-भोपाल	15.10.2026

रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

गाड़ी सं.	स्टेशन से-स्टेशन तक	वर्तमान मार्ग	परिवर्तित मार्ग	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
12627	क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेगलूरु -नई दिल्ली	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा	26.09.2026 से 14.10.2026
18237	कोरबा-अमृतसर	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा	26.09.2026 से 14.10.2026
12137	छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)-फिरोजपुर कैंट	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा	26.09.2026 से 14.10.2026
12779	वास्को द गामा-हज़रत निमामुद्दीन	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा	26.09.2026 से 14.10.2026
12780	हज़रत निमामुद्दीन -वास्को द गामा	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल	03.10.2026 से 15.10.2026
12618	हज़रत निमामुद्दीन -एरणाकुलम	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल	03.10.2026 से 15.10.2026
12716	अमृतसर-हुजूर साहिब नान्देड	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल	03.10.2026 से 15.10.2026
12617	एरणाकुलम-हज़रत निमामुद्दीन	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-ग्वालियर	भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर	25.09.2026 से 13.10.2026
12621	डॉ एम.जी.रामचंद्रन चेन्नई-नई दिल्ली	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-ग्वालियर	भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर	26.09.2026 से 14.10.2026
12919	डॉ. अम्बेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	मक्सी-संत हिरदाराम नगर-बीना-ग्वालियर	मक्सी-रुठियाई-गुना-ग्वालियर	27.09.2026 से 15.10.2026
12622	नई दिल्ली-डॉ एम. जी.रामचंद्रन चेन्नई	ग्वालियर-बीना-भोपाल	ग्वालियर-गुना-मक्सी-भोपाल	02.10.2026 से 14.10.2026
22181	जबलपुर-हज़रत निमामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	08.10.2026
12823	दुर्ग-हज़रत निमामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	08.10.2026
18477	पुरी-योग नगरी ऋषिकेश	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	07.10.2026
22407	अम्बिकापुर-हज़रत निमामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	08.10.2026
12807	विशखपट्टणम-हज़रत निमामुद्दीन	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	इटारसी-जबलपुर-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	14.10.2026
12707	तिरुपति-हज़रत निमामुद्दीन	जुझारपुर केबिन-भोपाल -बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	जुझारपुर केबिन-जबलपुर -ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	14.10.2026
12943	वलसाड-कानपुर सेंट्रल	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल	इटारसी-जबलपुर-मानिकपुर-प्रयागराज -कानपुर सेंट्रल	14.10.2026
22589	बनारस-हडपसर	बनारस-प्रयागराज-गोविन्दपुरी-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-इटारसी	बनारस-ब्लॉक हट के-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-जबलपुर-इटारसी	02.10.2026 से 14.10.2026
20104	गोरखपुर-लोकमान्य तिलक (ट.)	कानपुर सेंट्रल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-भोपाल-इटारसी	कानपुर सेंट्रल-हमीरपुर रोड-ओहन केबिन-जबलपुर-इटारसी	14.10.2026
01026	बलिया-दादर	मानिकपुर-खजुराहो-बीना-इटारसी	मानिकपुर-सतना-जबलपुर-इटारसी	14.10.2026
12643	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-हज़रत निमामुद्दीन	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	इटारसी-जबलपुर-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	13.10.2026
12148	हज़रत निमामुद्दीन-श्री छत्रपति शाहू महाराज (ट.) कोल्हापुर	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-भोपाल-इटारसी	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-ओहन केबिन-जबलपुर-इटारसी	15.10.2026
12174	माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-लोकमान्य तिलक (ट.)	कानपुर सेंट्रल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-भोपाल-इटारसी	कानपुर सेंट्रल-हमीरपुर रोड-ओहन केबिन-जबलपुर-इटारसी	15.10.2026
11408	लखनऊ-पुणे	कानपुर सेंट्रल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-भोपाल-इटारसी	कानपुर सेंट्रल-हमीरपुर रोड-ओहन केबिन-जबलपुर-इटारसी	15.10.2026
12107	लोकमान्य तिलक (ट.)-सीतापुर	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल	इटारसी-जबलपुर-ओहन केबिन-हमीरपुर रोड-कानपुर सेंट्रल	14.10.2026

रेलगाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	स्टेशन से/तक शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
12002	हज़रत निज़ामुद्दीन-रानी कमलापति	ललितपुर	15.10.2026
12001	रानी कमलापति-हज़रत निज़ामुद्दीन	ललितपुर	15.10.2026

रेलगाड़ियों की रिशेड्यूलिंग

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	रिशेड्यूलिंग समय	प्रारंभिक स्टेशन से रिशेड्यूलिंग	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
12174	माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-लोकमान्य तिलक (ट.)	120 मिनट	माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से	13.10.2026
22583	छपरा-लोकमान्य तिलक (ट.)	120 मिनट	छपरा से	13.10.2026
16031	डॉ एम.जी.रामचंद्रन चेन्नई-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	240 मिनट	डॉ एम.जी.रामचंद्रन चेन्नई से	14.10.2026
12652	हज़रत निज़ामुद्दीन-मदुरै	300 मिनट	हज़रत निज़ामुद्दीन से	15.10.2026
19484	सहरसा-अहमदाबाद	120 मिनट	सहरसा से	14.10.2026
11077	पुणे-जम्मू तवी	300 मिनट	पुणे से	14.10.2026
12650	हज़रत निज़ामुद्दीन-यशवंतपुर	240 मिनट	हज़रत निज़ामुद्दीन से	15.10.2026
12808	हज़रत निज़ामुद्दीन-विशखपट्टणम	180 मिनट	हज़रत निज़ामुद्दीन से	15.10.2026
18238	अमृतसर-बिलासपुर	180 मिनट	अमृतसर से	14.10.2026
12138	फिरोज़पुर कैंट-छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)	240 मिनट	फिरोज़पुर कैंट से	14.10.2026

रेलगाड़ियों का रेग्युलेशन

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	रेग्युलेशन समय	रेग्युलेशन ओवर	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
12138	फिरोज़पुर कैंट-छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)	90 मिनट	झाँसी मण्डल	10.10.2026 से 14.10.2026
12648	हज़रत निज़ामुद्दीन-कोयम्बत्तूर	90 मिनट	झाँसी मण्डल	14.10.2026
12650	हज़रत निज़ामुद्दीन-यशवंतपुर	90 मिनट	झाँसी मण्डल	10.10.2026 से 13.10.2026
12144	सुलतानपुर-लोकमान्य तिलक (ट.)	60 मिनट	झाँसी मण्डल	13.10.2026
11408	लखनऊ-पुणे	60 मिनट	झाँसी मण्डल	13.10.2026
12808	हज़रत निज़ामुद्दीन-विशखपट्टणम	60 मिनट	झाँसी मण्डल	10.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026
18238	अमृतसर-बिलासपुर	60 मिनट	झाँसी मण्डल	10.10.2026 से 14.10.2026
12630	हज़रत निज़ामुद्दीन-यशवंतपुर	30 मिनट	झाँसी मण्डल	14.10.2026
22686	चण्डीगढ़-यशवंतपुर	30 मिनट	झाँसी मण्डल	10.10.2026, 13.10.2026
20808	अमृतसर-विशखपट्टणम	60 मिनट	झाँसी मण्डल	15.10.2026
12511	गोरखपुर-तिरुवनन्तपुरम	60 मिनट	झाँसी मण्डल	15.10.2026
22403	पुदुच्चेरी-नई दिल्ली	60 मिनट	भोपाल मण्डल	15.10.2026

नोटः- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR | North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | 1882/26 (A)

उत्तर मध्य रेलवे

No: JHS-DY-CEE-C-T-02-2026/NIT | Date: 18.08.2026

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

उप मुख्य विद्युत अभियन्ता (निर्माण), उत्तर मध्य रेल, झाँसी, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से निम्न लिखित कार्य हेतु **एक पैकेट सिस्टम** पर ऑन लाइन (E-Tendering) के माध्यम से खुली निविदा आमन्त्रित करते हैं। निविदा दिनाँक **09.09.2026** को **11:00 बजे** तक website **http://www.ireps.gov.in** पर ऑन लाइन जमा की जा सकती है। निविदा के विवरण निम्नानुसार है:-

निविदा संख्या : E-Tender Notice No.-JHS-DY-CEE-C-T-02-2026

कार्य का नाम : झाँसी-बीना परियोजना के अंतर्गत तीसरी लाइन के संबंध में अगासोद यार्ड एवं अगासोद-बीना खंड के शेष ओएचई कार्यों का निष्पादन।

अनुमानित लागत : 37424587/- | **धरोहर राशि :** 748500/-

कार्य पूर्ण होने की अवधि : 03 माह हार्वेस्ट एवं मानसून अवधि सहित

निविदा खोलने का दिनांक : 09.09.2026 | **वैधता अवधि :** 60 दिन

नोटः- पूर्ण विवरण और निविदा जमा करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** देखें। **1904/26 (PH)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

मां शारदा लोक निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा-मुख्यमंत्री डॉ यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वप्रसिद्ध मां शारदा माता मंदिर में पूजन-अर्चन किया

प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर स्थित विश्वप्रसिद्ध मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि-विधानपूर्वक मां शारदा का पूजन-अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पूजन के बाद मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन द्वारा मां शारदा का चित्र भेट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, दर्शन व्यवस्था एवं मंदिर परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां शारदा की पावन नगरी मैहर देश-प्रदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां शारदा का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे और मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति एवं विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहीं प्रार्थना है। माँ शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी,जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह, राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, विधायक श्री विक्रम सिंह जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बहनों का सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मैहर से मिली लाड़ली बहनों को नैहर की नेग

लाड़ली बहनों को राखी के शगुन के साथ मिली सहायता राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को अंतरित किए 2148.30 करोड़ रुपए

बहनों को राखी से पहले मिला 1750 रु. का उपहार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों पर की पुष्प वर्षा, बंधवाई राखियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हॉकी खिलाड़ी अनन्या अवधिया और उन्नति पांडे के साथ अंतरित की लाड़ली बहनों को राखी

जनअभियान परिषद की नवांकुर सखियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भेंट की विशाल राखी

मुख्यमंत्री ने मैहर जिलेवासियों को दी 256 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर जिले के लिए की विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा

मैहर में हुआ राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहन-बेटियां हमारे घर-आंगन की रौनक हैं। बहन-बेटियों का मान-सम्मान और इनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हर महीने बहनों से उनकी रक्षा का वादा पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि शारदा मां के आशीर्वाद से मैहर अद्भुत स्थान है। बुंदेलखंड की वीरता के प्रतीक आल्हा-ऊदल मां शारदा के अनन्य भक्त हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उदारता और रिश्तों का सम्मान करने की परम्परा है। हम वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमने आज ही मैहर से प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को नैहर की नेग (राज्य सरकार का उपहार) दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मैहर में हुए राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में मां शारदा भवानी के दर्शन किए। इसके बाद इसी जिले की प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी सुश्री अनन्या अवधिया और सुश्री उन्नति पांडे के साथ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किश्त और रक्षाबंधन के विशेष शगुन के 250 रुपए (कुल 1750 रुपए) के रूप में 2 हजार 148 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से बैंक खातों में अंतरित किये। उल्लेखनीय है कि जून 2023 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से अगस्त 2026 तक 39 किश्तों में लाड़ली बहनों के खातों में 63 हज़ार 248 करोड़ रुपये की सहायता राशि अंतरित की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना बहनों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए सशक्त बनी है। रक्षाबंधन का धागा भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। राज्य सरकार बहनों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत हर माह बहनों का राशि भेजी जा रही है। प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख लाड़ली बहनों का आशीर्वाद सरकार को मिल रहा है। हर साल रक्षाबंधन से पहले बहनों को 250 रुपए का शगुन भी भेजा जा रहा है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर जिले में लगभग 256 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले की विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों तथा योजनाओं की उपलब्धि पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी बहनें अपने जीवन में माता-पिता के घर को संवारती हैं और विवाह के बाद पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेती हैं। बहनों का यह त्याग वंदनीय है। भारतीय संस्कृति में मां-बेटियां परिवारों की धुरी हैं। माताएं अपनी चिंता नहीं कर पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। राज्य सरकार ने अगले 5 साल तक लाड़ली बहनों को राशि देने का निर्णय कैबिनेट में लिया है। अगले 5 वर्ष में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि बहनों को मिलेगी। लाड़ली बहना योजना की राशि परिवार की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। राज्य सरकार बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। हमारी बहनें स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। रोजगार परक उद्योगों में काम करने पर बहनों को वेतन में पाँच हजार रुपए अलग से लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने महाकाल के महाकाल लोक के बाद प्रदेशभर में देवस्थानों के विकास का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में श्रीराम वन गमन पथ, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की धारा को अविरल रखने और विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ के कार्य मंजूर किए गए हैं। मैहर में 9 करोड़ रुपए की लागत से मां शारदा लोक निर्माण के पहले चरण का भूमि-पूजन आज हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। राज्य सरकार ने 19 धार्मिक स्थानों पर शराब दुकानें बंद की हैं। भावी पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को नशे से दूर रखने और उनके बेहतर भविष्य के लिए बच्चों से संवाद हमेशा बनाए रखें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष में लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ा रही है। विंध्य क्षेत्र को किसानों को बरगी नहर के पानी का लाभ मिलेगा। किसानों को रात के साथ दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गौपालन और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए संकल्प पारित किया है।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं :-

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर जिले में चल रहे विकास कार्यों को और भी गति देते हुए घोषणा करते हुए कहा कि -

मैहर जिले के बदेरा पहाड़ में 132 केवीए का सब स्टेशन बनाया जायेगा।

मैहर में 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्टेडियम बनाया जायेगा।

लिलजी जलाशय का 50 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा।

मैहर में एक बड़ा सर्व सुविधायुक्त अस्पताल बनाया जाएगा।

मैहर में 5000 गौवंश क्षमता की बड़ी गौशाला बनेगी।

घुनवारा में आईटीआई संस्थान बनेगा, स्कूल का उन्नयन किया जाएगा।

लाड़ली बहना सम्मेलन में आईं आल्हा गायकों की सभी समितियों को 25-25 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।

लोकार्पण-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में 48 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सांदीपनि विद्यालय, 7 करोड़ 58 लाख की लागत से ताला में शासकीय महाविद्यालय भवन, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अमरपाटन में 30 सीटर बालक छात्रावास तथा आवास का लोकार्पण किया। इस क्रम में 21 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बठिया-चोरहटा, बंधी बैरागल, खमरिया-पनिहा-कुशमी-झुकेही और ग्राम पंचायत जमताल में सड़क निर्माण कार्यों तथा 19 करोड़ से अधिक की लागत से जनपद पंचायत मैहर, अमरपाटन और रामनगर में जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़े 1 हजार 69 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पुलिस कंट्रोल रूम, 1 करोड़ 47 लाख की लागत से जूरा में नवीन शासकीय हाईस्कूल भवन और 59 लाख रुपये की लागत से परशुराम धर्मशाला भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 151 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके अंतर्गत लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से मैहर में धनवाही माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन शामिल है, इससे 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 41 करोड़ की लागत से रामनगर में सांदीपनि विद्यालय और लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से शारदा माता लोक के प्रथम चरण के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री तथा मैहर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले मैहर को बड़े विकास कार्यों की सौगात मिली है। मां शारदा लोक निर्माण के पहले चरण के कामों का भूमिपूजन भी आज हो गया है। माई की कृपा से मैहर जिले का तेजी से विकास हो रहा है।

क्षेत्रीय सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत में पहली बार जनसमस्या निवारण के लिए हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को दूर करने की पहल की है। रक्षाबंधन से पहले मां शारदा देवी के दरबार से प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1750 रुपए की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में बरगी नहर का कार्य तेजी से पूरा हुआ। इससे मैहर सहित विंध्य क्षेत्र को लाभ मिलेगा। आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मां शारदा देवी लोक के प्रथम चरण का शिलान्यास किया। मैहर को आज 250 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाणसागर में इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इन सभी प्रयासों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने मांग रखी कि टाइगर कॉरिडोर में मैहर और सतना जिले को भी शामिल किया जाए।

मैहर विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि मैहर नया जिला बना है। यहां शहर के बाहर रिंग रोड, अस्पताल, महाविद्यालय और ओलिंपिक स्तर का स्टेडियम बनाए जाने की आवश्यकता है। मैहर में 20 साल से विकास की गति रुकी हुई थी, लेकिन अब यह जिला तेजी से तरक्की कर रहा है।

कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पूर्व मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, विधायक श्री विक्रम सिंह, विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामखेलावन सिंह कोल, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विकास यादव, समाजसेवी श्रीमती नंदिता पाठक, जिलाध्यक्ष श्री कमलेश सोहाने सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होमगार्ड आपदा यंत्रों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत होमगार्ड द्वारा प्रदर्शित किए गए आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं बचाव कार्य में उपयोग होने वाले आधुनिक संसाधनों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान होमगार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विभिन्न आपदा प्रबंधन यंत्रों की कार्यप्रणाली एवं उनके उपयोग की जानकारी दी। इन उपकरणों का उपयोग बाढ़, आगजनी, भवन दुर्घटना, सड़क हादसे तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों में किया जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों एवं जवानों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के अधिकारी-जवान उपस्थित रहे।

भव्य, दिव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं हमारे संकट मोचक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 945.20 करोड़ से बनने वाले 5.30 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया भूमि-पूजन

जीवन रक्षक किट और प्रमाण पत्र भी किए वितरित

उज्जैन की कालिदास अकादमी में हुआ होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आज उज्जैन को 945.20 करोड़ रुपए लागत के नवीन एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। यह 5.30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन की बड़ी सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा मेला होगा। बीते सोमवार को नागपंचमी पर श्रद्धालुओं के प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे। बेहतर प्रबंधन के लिए उज्जैन का पूरा प्रशासन बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को उज्जैन की कालिदास अकादमी में आयोजित होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सिंगल क्लिक से नवीन एलिवेटेड कारीडोर का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1980 के उज्जैन सिंहस्थ में स्काउट एंड गाइड मेंबर रहा था। सिंहस्थ 2016 के आयोजन में कई प्रकार की सावधानियां बरती गईं। रामघाट पर सुविधाएं बढ़ाई गईं, उज्जैन में बायपास निर्माण की जरूरत महसूस की गई। उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का निर्माण से धार्मिक तीर्थाटन बढ़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन निर्माण की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। उज्जैन और इंदौर में मल्टी एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे विकास कार्यों को पूरा करने में आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाता है। नया कॉरिडोर महाकाल मंदिर तक जाने के लिए वैकल्पिक रोड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। उज्जैन में रेल और नदी पर आवश्यकतानुसार 7 ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाइवे का काम 80 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए हम तत्पर हैं। होमगार्ड के जवानों और पुलिस-प्रशासन के साथ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर प्रबंधन किए जाएंगे। होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन पर लोगों की जान-माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। ये सभी साथी हमारे संकट मोचक हैं, समाज के सच्चे नायक-नायिका हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2016 के आयोजन में 7 किलोमीटर के घाट थे, आगामी सिंहस्थ में शिप्रा के 35 किलोमीटर के घाट होंगे, जहां श्रद्धालु स्नान करेंगे। उज्जैन में 300 सर्पमित्रों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह शोध का विषय है कि सभी ज्योतिर्लिंग के आसपास सांपों की संख्या अधिक होती है। इसलिए उज्जैन में स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, जिसका लोकार्पण जल्द किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर प्रत्येक पंचायत और थाना स्तर पर एक प्रशिक्षित सर्प मित्र उपलब्ध हो। जो सांपों को आवासीय क्षेत्रों से पकड़कर जंगलों में छोड़ें। हमारा प्रयास है कि मनुष्य और सर्प दोनों सुरक्षित रहें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में होंगे शामिल

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार 20 अगस्त को संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्लोबल स्किल्स पार्क का भ्रमण करेंगे। साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट और चर्चा करेंगे। साथ ही कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करने से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।